खबर पेज 6 पर

गंभीर समाचार

समय–समाज–संस्कृति

खबर पेज 7 पर

होली हुड़दंग पेज पर पढ़ें समाज की कुछ विशिष्ट हस्तियों के नाम के साथ 'विशेष' पदवी

वर्ष -12 | अंक–23 | पाक्षिक समाचार पत्रिका | कोलकाता, सोमवार 16 – 28 फरवरी 2026 | मूल्यः 5 रुपये | RNI No.WBHIN/2014/59321, ISSN No. 2456/3005 Kolkata | कुल पृष्ठ – 8

सुविचार

- इतना काम करिये की काम भी आप का काम देखकर थक जाय।
- यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे, तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सीखा देती है।
- अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है।

शेरो-शायरी

- कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती ओर धर्म से बड़ी कोई जाती नहीं होती
- अकेली रात बोलती बहुत है लेकिन सुन वही सकता है जो खुद भी अकेला हो
- बहुत हिम्मत वाली हूं.. लेकिन कभी कभी हार जाती हूं कभी बाते सुन कर कभी लेहजा देख कर।

एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट 2026 जारी

***पहल चरण में 7 लाख वोटर्स के नाम डिलीट किए गए *7.08 करोड़ वोटर को 3 कैटेगरी में बांटा**

निज संवाददाता : भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की तय डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद बंगाल के लिए वोटर लिस्ट का पहला हिस्सा जारी किया। हालांकि इस रिपोर्ट को पब्लिश करते समय पोल पैनल ने लिस्ट को ऑनलाइन पब्लिश नहीं किया था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि पिछले दिसंबर में ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद राज्य में 7.08 करोड़ वोटर्स में से अब तक लगभग 7 लाख को डिलीट किया जा चुका है, और बाकी 60,60,475 को न्यायिक निर्णय के तहत मार्क किया गया है।ड्राफ्ट रोल के बाद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी या अनमैप्ड कैटेगरी के तहत मार्क किए जाने के वेरिफिकेशन के लिए ये लगभग 60 लाख मामले अभी भी पेंडिंग हैं। पिछले दिसंबर में पब्लिश हुए ड्राफ्ट रोल में 58 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम डिलीट किए गए थे।चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि जब तक एसआईआर प्रोसेस पूरा होगा, तब तक डिलीट किए गए वोटर्स की संख्या अभी की संख्या से ज़्यादा हो सकती है। बांकुड़ा जिले में अब तक करीब 1.18 लाख वोटर्स के नाम फाइनल रोल से हटा दिए गए हैं। नदिया में करीब 2.73 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। उत्तर कोलकाता में फाइनल ड्राफ्ट में करीब 17,000 वोटर्स के नाम हटा दिए गए, जिससे एसआईआर प्रोसेस शुरू

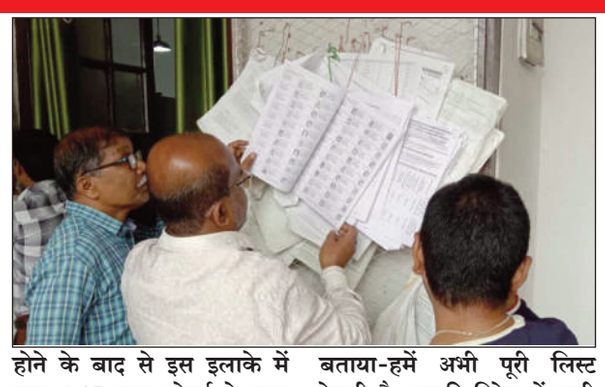

होने के बाद से इस इलाके में कुल 4.07 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। दक्षिण कोलकाता में यह संख्या 3,207 है, जबकि 78,675 और वोटर्स की किस्मत का फैसला अभी बाकी है।बैरकपुर से तृणमूल सांसद पार्थ भौमिक ने शनिवार को बताया-हमें अभी पूरी लिस्ट देखनी है। इसकी डिटेल में स्टडी किए बिना कोई कमेंट करना गलत होगा। नैहाटी (उत्तर 24-परगना में) से मुझे जो पता चला है, उसके हिसाब से असली वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। मुझे सात डॉक्टर, रेलवे एम्प्लॉई और दूसरे लोग गायब मिले हैं। और भी मिल जाएंगे।बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार-बार दावा किया है कि जब फाइनल लिस्ट पब्लिश होंगी तो 1.2 करोड़ वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिए जाएंगे।उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में, फाइनल रोल में 11,96,651 नाम थे, जिससे जिले में कुल 1,02,835 नाम हटाए गए हैं, ऐसा अधिकारियों ने कहा। अपडेटेड रोल की हार्ड कॉपी शनिवार को कई जिलों में डाल दी गईं, जबकि आखिरी रिपोर्ट आने तक लिस्ट तय पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं थीं।चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि नाम मुख्य रूप से मौत, माइग्रेशन, डुप्लीकेशन और पता न चलने की वजह से हटाए गए, जबकि डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी के बाद नाम जोड़े गए।7.08 करोड़ वोटर को 3 श्रेणियों में बांटा जायेगावोटर लिस्ट के प्रकाशन से 7.08 करोड़ मतदाताओं को 'स्वीकृत', 'हटाये गये' या 'विचाराधीन' के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा। विचाराधीन की श्रेणी में वैसे वोटर्स को रखा गया है, जिनके नामों की न्यायिक अधिकारियों द्वारा वर्तमान में जांच की जा रही है। सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी होने के बाद पता चलेगा कि किन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किये गये हैं और किनके नाम हटाये गये हैं।चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट जारी करने में लगे 116 दिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 को मतदाताओं के बीच जनगणना **(शेष पृष्ठ 2 पर)**

होली की शुभकामना

रंगो का त्योहार होली प्रेम, उमंग और भाईचारे का प्रतीक है। इस पावन पर्व के मौके पर **'गंभीर समाचार'** के सभी पाठकों, विज्ञापनदाताओं और शुभाकांक्षियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना। हमें पूरी उम्मीद है, हमेशा की तरह आपका प्यार और स्नेह मिलता रहेगा।

-संपादक

सोशल मीडिया पर लग सकती है पाबंदी!

ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के रास्ते पर भारत?

निज संवाददाता : क्या भारत भी ऑस्ट्रेलिया की तरह बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करेगा? सीधे तौर पर कहे बिना, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका इशारा किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ उम्र के आधार पर पाबंदियों पर बातचीत चल रही है। साथ ही, डीपफेक भी बातचीत के केंद्र में हैं। सरकार भविष्य के लिए रोडमैप तय करने के लिए यह बातचीत कर रही है। बच्चों को सोशल मीडिया के नुकसानदायक असर से बचाने और यूज़र्स को नुकसान से बचाने के लिए मज़बूत नियम और कानून बनाने की ज़रूरत है। अश्विनी ने ज़ोर देकर कहा कि कोई भी कंपनी, चाहे वह नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, मेटा हो या एक्स, उसे भारत के कानूनी ढांचे और संविधान का पालन करना होगा। उनके मुताबिक, डीपफेक की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इससे सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। अश्विनी ने कहा-उम्र के आधार पर पाबंदियों और डीपफेक को सुलझाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत चल रही है, ताकि सही उपाय तय किए जा सकें। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रसारण मंत्री का मानना है कि डीपफेक पर और कड़े कंट्रोल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा-मुझे लगता है कि हमें डीपफेक पर और सख्त कंट्रोल की ज़रूरत है। यह एक बढ़ती हुई समस्या है। बेशक, बच्चों और हमारे समाज को इस नुकसान से बचाने की ज़रूरत है। हम सोच रहे हैं कि अब तक जो कंट्रोल हैं, उनसे आगे और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी भी इस मुद्दे की गहराई से समीक्षा कर रही है। अश्विनी ने कहा कि संसद के सभी सदस्यों को इस पर आम सहमति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों ने सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए पाबंदियों की ज़रूरत को माना है। पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। यह नियम फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम समेत 10 पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू किया गया है। 16 साल से कम उम्र के 1 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट्स की पहचान करके उन्हें संबंधित एजेंसियों ने ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बल्कि फ्रांस समेत कुछ देशों ने भी यही रास्ता अपनाया है।

बीजेपी ने बनाया '170 सीटों का मिशन'

बंगाल में ममता का किला फतह करने की पुरजोर तैयारी

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल की सियासत में 2026 के विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले चुनावी लड़ाई का शंखनाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अब 120 नहीं, बल्कि 170 विधानसभा सीटों पर फोकस तय किया है। लक्ष्य साफ है कि करीब 6.5 फीसदी वोट का अंतर खत्म कर सत्ता के करीब पहुंचना। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आक्रामक अभियान चलाया, लेकिन 77 सीटों पर सिमट गई। वोट प्रतिशत 38.15 फीसदी रहा, जबकि टीएमसी 44.91 फीसदी वोट के साथ 211 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी। दोनों के बीच करीब 6.5 फीसदी का अंतर रहा। अब बीजेपी ने 160 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं, जहां उसे जीत की संभावना दिख रही है। पार्टी का मानना है कि अगर 5 से 7 फीसदी का स्विंग हो जाए, तो तस्वीर बदल सकती है। करीब 91 हजार बूथों में लगभा सही जगह समितियों का गठित करने का दावा है। जिलावार वॉर-रूम तैयार हो रहे हैं। डेटा एनालिसिस, पिछली हार-जीत का मार्जिन, जातीय-सामाजिक समीकरण और महिला वोटसबका अलग-

अलग आकलन किया जा रहा है। बीजेपी का मानना है कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं,बल्कि बंगाल में राजनीतिक संस्कृति बदलने का चुनाव होगा। चुनाव प्रबंधन में माहिर नेताओं को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल संगठन में गुटबाजी खत्म करने और मैसेजिंग कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव और बिप्लब देब जैसे नेता चुनावी गणित और उम्मीदवार चयन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से आए अनुभवी नेताओं को प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में मंडल और जिला स्तर पर तैनात किया गया है। इनकी जिम्मेदारीकम मार्जिन से हारी सीटों पर खास रणनीति बनाना, अंदरूनी मतभेद सुलझाना, और बूथ स्तर पर मतदाता संपर्क बढ़ाना है। बीजेपी इस बार सीधे तौर पर व्यक्तिगत हमलों से बचने की रणनीति पर भी काम कर रही है। फोकस वंशवाद, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और रोजगार के मुद्दों पर रहेगा। टीएमसी का कहना है कि बंगाल की जनता विकास और सामाजिक योजनाओं के साथ है। 2026 में भी जनता दीदी के नेतृत्व पर भरोसा करेगी। बीजेपी महिला सुरक्षा को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आरजी कर और अन्य चर्चित घटनाओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। रोजगार, उद्योगों की कमी और पलायन को भी नैरेटिव का हिस्सा बनाया जा रहा है। साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची साफ होने से बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। पार्टी का आरोप है कि पिछली बार डुप्लीकेट और फर्जी वोटिंग से नुकसान हुआ। 160 सीटों का टारगेट सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। बीजेपी अब विपक्ष की भूमिका से आगे बढ़कर सत्ता की दावेदार बनना चाहती है। हालाकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 6 से 7 फीसदी का वोट स्विंग आसान नहीं होता। इस बीच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और बंगाल के माइग्रेंट वर्कर्स का मामला टीएमसी ने और बड़े स्तर पर उठाना शुरू कर दिया है। 2026 का चुनाव बंगाल में सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं होगा,बल्कि नैरेटिव और संगठनात्मक ताकत की परीक्षा भी होगा। सवाल वही है, क्या मिशन 160 से बीजेपी टीएमसी के किले में सेंध लगा पाएगी? या फिर सत्ता की चाबी एक बार फिर ममता के हाथ में ही रहेगी। 2021 में 77 सीटों तक पहुंचने वाली बीजेपी इस बार माइक्रो-मैनेजमेंट, बूथ स्ट्रक्चर और प्रवासी कार्यकर्ता मॉडल के जरिए बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, रोजगार और उद्योगइन मुद्दों के सहारे पार्टी नैरेटिव बदलने की कोशिश में है।

दुनिया भर में 40 और भारत में 26 फीसदी नौकरियां निगल सकता है एआई

- आईएमएफ के अध्ययन में हुआ खुलासा
- विकसित देशों में इसका इंपैक्ट सबसे ज़्यादा होगा

निज संवाददाता : दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ने से जॉब मार्केट पर असर पड़ना शुरू हो गया है। मल्टीनेशनल कंपनियां कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की राह पर चल रही हैं। धीरे-धीरे बेरोजगारी बढ़ रही है। हालात को भांपते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जल्दबाजी में इस पर एक स्टडी की। इसमें पाया गया है कि आने वाले समय में दुनिया भर में 40 फीसदी नौकरियां एआई निगल सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में नहीं, बल्कि अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देशों में इसका असर सबसे ज़्यादा होगा। आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एआई को लेकर चेतावनी दी थी। सर्वे के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने दिखाया कि एआई भारतीय मार्केट में 26 फीसदी नौकरियों पर असर डाल सकता है। सबसे ज़्यादा खतरा एंट्री-लेवल कर्मचारियों को है, जिन्होंने अभी-अभी एग्जाम पास करके जॉब मार्केट में एंट्री की है। असल में, एआई के ज़रिए उनका काम आसानी से हो रहा है। इस वजह से, युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा बेरोज़गारी की कगार पर है।

सुनामी का झटका

आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना के मुताबिक, एआई भारत समेत पूरी दुनिया के जॉब मार्केट पर सुनामी की तरह असर डालने वाला है। इसकी लहरें अभी से उठनी शुरू हो गई हैं। स्टडीज़ कहती हैं कि विकसित देशों में 60 फीसदी लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। इसलिए, अगर सही नीतियां नहीं अपनाई गईं, तो कम अनुभवी युवा पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की इस धारा में सबसे पहले बह जाएगी। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। यहां जॉब मार्केट भी बहुत बड़ा है। हर साल लाखों युवा जॉब मार्केट में आ रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि अकेले 2023-24 में 19 मिलियन युवा नई नौकरियों से जुड़ेंगे। क्रिस्टालिना का मानना है कि एआई की रफ़्तार को रोकने का कोई तरीका नहीं है। बल्कि, इसे अपनाना होगा। अगर एआई को एक खास प्लान के ज़रिए लागू किया जाए,

तो यह एक वरदान साबित हो सकता है। एआई और एआई-बेस्ड टेक्नोलॉजी भारत की जीडीपी को हर साल 0.7 फीसदी बढ़ा सकती हैं।

इसका सॉल्यूशन क्या है?

टीसीएच रिसर्च के सीनियर साइंटिस्ट अनिर्वाण दत्ताचौधरी का मानना है कि एआई-सुनामी के असर से निपटने का एकमात्र तरीका एआई का इस्तेमाल करना है। जो लोग टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, वे बदलते हालात में आगे रहेंगे। इस बारे में, अनिरबन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जाने-माने रेडियोलॉजिस्ट कर्टिस लैंगलोट्ज़ के हवाले से कहा-जेफरी हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता था, ने 2016 में एक कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि रेडियोलॉजिस्ट की अब ज़रूरत नहीं है। डीप लर्निंग पांच साल के अंदर रेडियोलॉजिस्ट से कहीं बेहतर काम करेगी। इस थ्योरी को चुनौती देते हुए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लैंगलोट्ज़ ने 2018 में कहा था कि एआई रेडियोलॉजिस्ट की जगह नहीं ले पाएगा। लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट एआई का इस्तेमाल करेंगे, वे उन लोगों की जगह ले लेंगे जो एआई का इस्तेमाल नहीं करते। यही बात किसी भी दूसरे प्रोफेशन पर लागू होती है। अनिर्वाण आईएमएफ सर्वे के नतीजों से हैरान नहीं हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए उनका मैसेज है-एआई से डरने के बजाय, हमें यह देखना होगा कि हम एआई का इस्तेमाल करके अपने काम को कैसे बेहतर बना सकते हैं।

एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत

जादवपुर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अमित कोनेर का मानना है कि एआई से निपटने के लिए स्कूल और कॉलेज लेवल पर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। अमित उनमें से एक हैं। कोलकाता में एआई की प्रैक्टिस शुरू करने वालों में से एक अमित ने कहा-इतने लंबे समय से चला आ रहा एजुकेशन सिस्टम अब बदलते हालात में ठीक नहीं है। जो काम एआई नहीं कर सकता, उन्हें स्टूडेंट्स को ज़्यादा सिखाया जाना चाहिए। अमित ने कहा-हर साल, एमसीए या बीई डिग्री वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग का काम करने आते हैं। अब एआई उन कामों को बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कर रहा है। बड़े ऑर्गनाइज़ेशन में ऐसे काम एआई से किए जा रहे हैं। उन्हें अब अलग से हायर नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हमें कॉलेज लेवल पर शिक्षा प्रणाली में बदलाव की ज़रूरत है। प्रोग्रामिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना काफ़ी नहीं होगा। बल्कि, हमें प्रोग्राम बनाने के लिए ज़रूरी नंबर सीखने होंगे, जो एआई आसानी से नहीं बना सकता। भविष्य में भी जॉब्स होंगी, लेकिन उनका टाइप बदल जाएगा।

26 फीसदी का भविष्य क्या है

आईएमएफ का मानना है कि भारत में जो 26 फीसदी लोग रसातल के किनारे खड़े हैं, अगर सुनामी आती है तो उनका भविष्य क्या होगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक, उन्हें बदलते जॉब मार्केट के हिसाब से खुद को ढालना होगा। अमित का मानना है कि अलग से ट्रेनिंग इस खास सेगमेंट के लिए एडवांस्ड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। उन्होंने समय की मांग के हिसाब से स्कूलों में जॉब-ओरिएंटेड कोर्स शुरू करने की भी बात की है।

आईएसआई कोलकाता के प्रोफेसर भक्ति दास का मानना है कि समय की मांग सिर्फ पुरानी नौकरियां बचाना ही नहीं है, बल्कि नई नौकरियां बनाना भी है। क्योंकि जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां नौकरियां देंगी, वे अपने मुनाफे के अलावा कुछ नहीं देखेंगी। **(शेष पृष्ठ 2)**

बंगाल में बीजेपी निकालेगी 'परिवर्तन रथ यात्रा'

♦1 मार्च को कूचबिहार से होगा आगाज ♦समापन रैली में शामिल होंगे पीएम मोदी

रथ यात्रा 1 और 2 मार्च से शुरू होगी। 1 मार्च को उत्तर बंगाल के कूचबिहार और साउथ बंगाल के कृष्णानगर, दक्षिण गड़बेता, रायदिघी, कुल्टी से रथ यात्रा शुरू होगी। अगले दिन यानी 2 मार्च को इस्लामपुर, संदेशखाली, हसनाबाद, आमता से रथ यात्रा शुरू होगी। 3 मार्च को डोल और 4 मार्च को होली है। इसलिए इन दो दिनों में रथ यात्रा बंद रहेगी। फिर 5 से 10 मार्च तक हर विधानसभा क्षेत्र में 5 हजार किलोमीटर से ज़्यादा की रथ यात्रा होगी।

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन रथ यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बताया कि यात्रा 1 मार्च को कूच बिहार साउथ से शुरू होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी बीच बीजेपी ने चुनावों के लिए अपने कैंपेन के तहत पश्चिम बंगाल में 'परिवर्तन रथ यात्रा' निकालने का फैसला लिया है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। यात्रा का समापन कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होगा और पीएम मोदी यहां एक बड़ी जससभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बताया कि परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में, राज्य में लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो गए हैं और करप्शन ने एक इंस्टीट्यूशनल रूप ले लिया है। आने वाले चुनावों को देखते हुए और तृणमूल कांग्रेस को हराने के मैसेज के साथ लोगों तक पहुंचने के लिए, पूरे राज्य में परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 9 यात्राएं निकाली जाएंगी। इस यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। समिक भट्टाचार्य ने बताया कि यात्रा 1 मार्च को कूचबिहार दक्षिण, कृष्णानगर दक्षिण, गड़बेता, रायदिघी और कुल्टी से और 2 मार्च को इस्लामपुर, संदेशखली, हसन और आमता से शुरू होगी। यह प्रोग्राम 3 मार्च और 4 मार्च को डोल यात्रा और होली के मौके पर रोक दिया जाएगा। 5 से 10 मार्च तक, यह प्रोग्राम राज्य के अलग-अलग विधानसभा इलाकों का दौरा करते हुए कुल 5,000 किमी. से ज्यादा का सफर तय करेगा। इस यात्रा के दौरान करीब 60 बड़ी और 300 से ज्यादा छोटी सार्वजनिक सभा करने का प्लान है। भट्टाचार्य के मुताबिक, हर विधानसभा इलाके में रथ, झांकी और कैंपेन होंगे। यह यात्रा मार्च के आखिर में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक मीटिंग के साथ खत्म होगी। मार्च के दूसरे सप्ताह के आखिर में 14/15 मार्च को यह समापन रैली होने की संभावना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भट्टाचार्य ने भी इशारा किया है कि यात्राओं के उद्घाटन स्टेज पर भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रह सकते हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों से इस यात्रा में हिस्सा लेने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी आमने-सामने हैं। बीजेपी इस बार चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी के तमाम नेता टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को घेरे हुए हैं। माना जा रहा है कि परिवर्तन रथ यात्रा भी बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पिछले करीब डेढ़ महीने से करीब 3 बार बंगाल जा चुके हैं। बुधवार को एक बार फिर वह बंगाल जा रहे हैं।

भारत में नौकरिया निगल सकता है एआई...

(प्रथम पृष्ठ का शेषांश)

इसलिए, युवा पीढ़ी को नई स्किल्स सीखनी चाहिए। उनके शब्दों में-अगर एआई का सही इस्तेमाल किया जा सके, तो देश को फायदा होगा। युवा पीढ़ी को हालात के हिसाब से ढलने की काबिलियत और लचीली सोच की ज़रूरत है। भविष्य की नौकरियां बहती नदी की तरह होंगी। एक तरफ कम होंगी, दूसरी तरफ बढ़ेंगी। जो ढल पाएंगे, वही बचेंगे।

सरकारी पॉलिसी

एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई-सुनामी में आने वाली आपदाओं को रोकने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अमिता चटर्जी ने कहा-हमने हमेशा देखा है कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है, तो नौकरियां एक तरफ जाती हैं, और नौकरियां दूसरी तरफ आती हैं। इस मामले में भी ऐसा ही होगा। इसके लिए तैयारी की ज़रूरत है। कुछ नौकरियों के जाने की संभावना ज़्यादा होती है, और कुछ मामलों में, नई पोस्ट, नई नौकरियां जो रोल बनाए जा सकते हैं, उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। यह पक्का करना होगा कि एक तरफ जिनकी नौकरी चली जाए, उन्हें दूसरी तरफ भी नौकरी मिले। यह सरकार के ज़रिए किया जाना चाहिए। प्राइवेट कोशिशें फ़ायदेमंद नहीं होंगी। अमित के स्वागत वाले लहज़े में कहा गया- बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सी पॉलिसी अपना रहे हैं। अगर कोई खास प्लान और पॉलिसी है, तो एआई एक नया लेबर मार्केट बनाएगा और लाखों लोगों को आर्थिक क्षेत्र में लाएगा। भारत को अपना एआई मॉडल बनाने और उसे भारतीय संदर्भ में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।

क्या एआई सही है

बहुत से लोग अभी भी एआई को लेकर चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनके मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कभी भी 100 फीसदी भरोसेमंद नहीं हो पाएगी। कुछ को इतना भरोसा नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि एआई में कई कमियां हैं। हालांकि, टीसीएस के अनिर्वाण का मानना है कि दुनिया कमियों का रोना बंद नहीं करेगी। उनके शब्दों में-एआई अभी भी कमियों से मुक्त नहीं है। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी समय के साथ बेहतर और ज़्यादा एडवांस्ड होती जाती है। भले ही एआई की बेहतरीन क्वालिटी 100 फीसदी न हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनियां अपने फायदे के लिए इस पर निर्भर रहेंगी। जब टेक्नोलॉजी 100 फीसदी सही हो जाएगी, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे - दुनिया ऐसे नहीं चलती। हालांकि, अनिर्वाण यह भी मानते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी के पीछे इंसान का हाथ होना चाहिए।

मशीन नहीं

अमिता यह मानने को तैयार नहीं हैं कि मशीनों की वजह से समाज की इंसानी ज़रूरतें खत्म हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी में सुधार के बावजूद, लोगों के पास कुछ कामों का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए उनका मानना है कि भविष्य में जितनी नौकरियां जाएंगी, उतनी ही नई नौकरियां भी बनेंगी। एक उदाहरण देते हुए अमिता ने कहा-जब बैंकिंग सेक्टर में सब कुछ पहली बार ऑटोमेटेड हुआ था, तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब उस स्थिति को संभाल लिया गया है। इस मामले में भी, जिन लोगों की नौकरियां जाने की संभावना है, उन्हें फिर से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। अगले कुछ दिनों में, हम जॉब मार्केट के शुरुआती स्टेज पर आईएमएफ सर्वे का असर देखेंगे। लेकिन इंसानों की भूमिका का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।

भारत कहां खड़ा है

एमिटी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफ़ेसर पुशनकुमार दत्ता का मानना है कि एआई का डर असलियत से ज़्यादा दिखावा है। हालांकि, एआई का कमर्शियलाइज़ेशन दुनिया भर में वर्कफ़्लो को बदल रहा है। भारत में भी तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। नहीं तो, एआई इस देश में न्यू नॉर्मल नहीं बन सकता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम के डेटा का ज़िक्र करते हुए पुशन ने कहा-2022 में एआई इस्तेमाल करने वाले बिज़नेस का हिस्सा 55 फीसदी था, अब यह बढ़ गया है। 88 फीसदी तक। एक तरफ, इससे नए मौके बन रहे हैं, तो नौकरियों को लेकर भी चिंता है। एंट्री-लेवल वर्कर भारत में वर्क सिस्टम की रीढ़ हैं। चिंता मुख्य रूप से उन्हीं की है। अब सवाल यह है कि देश की सरकार इस रीढ़ को बचाने के लिए एआई का कितना इस्तेमाल करने को तैयार है। पुशन का मानना है कि भारत अभी एआई टेक्नोलॉजी के फायदे के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने की ज़रूरत है। आंकड़े दिखाते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में तमिलनाडु अभी भारत में सबसे एडवांस्ड है। उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। फिर, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा डिजिटाइजेशन में क्रमशः आगे हैं। अगर चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे के आईटी हब का इस्तेमाल करके तुरंत एआई-फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके, तो बहुत सारी समस्या हल हो सकती है। समय के साथ, यह ज़रूरी है कि साइंस और टेक्नोलॉजी बेहतर हों। मशीनें इंसानी काम कम करती हैं। लेकिन एआई ने इंसानी सभ्यता को वरदान और श्राप के ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है, जो एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर रहा है। टेक्नोलॉजी को छोड़ना कोई हल नहीं हो सकता। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसके लिए बने संकट को दूर करने के लिए भी करना होगा। तभी युवा पीढ़ी आने वाले अंधेरे में रोशनी की दिशा खोज पाएगी।

ब्लॉक-स्तर पर खुलेंगे 430 मॉडल स्कूल

राज्य में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने की पहल

निज संवाददाता : राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए करीब 2,400 करोड़ रुपये की लागत से 430 मॉडल स्कूल खोलने जा रही है। जिन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से बनाया जाएगा। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, इको-फ्रेंडली बिल्डिंग और मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। हर ब्लॉक में एक और 87 पिछड़े ब्लॉक में दो स्कूल बनाने का प्लान बनाया गया है। नवान्न में कैबिनेट मीटिंग के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा-बांग्ला अब शिक्षा के क्षेत्र में देश में सबसे आगे है। उस स्थिति को और मजबूत करने के लिए, राज्य ने स्कूल शिक्षा का विस्तार प्रोजेक्ट शुरू किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इस प्रोजेक्ट की कुल लागत का 70 फीसदी वहन करेगा। बाकी 30 फीसदी राज्य देगा। इन स्कूलों में अंग्रेजी और बंगाली दोनों पढ़ाई जाएंगी। हालांकि, कोई नई स्कूल बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी। मौजूदा स्कूलों में से, हर ब्लॉक में एक स्कूल की पहचान करके उसे मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए ब्रात्य ने लिखा- राज्य कैबिनेट ने स्कूल एजुकेशन को बेहतर बनाना या स्कूल एजुकेशन का विस्तार नाम के एक बड़े एजुकेशन प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2,349.78 करोड़ रुपये होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में, यह प्रोजेक्ट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाएगा, शिक्षा में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाएगा और स्कूल लेवल पर मॉडर्न साइंटिफिक तरीकों को शुरू करेगा। आसान शब्दों में कहें तो, इस प्रोजेक्ट का मकसद राज्य में स्कूली शिक्षा को और मॉडर्न और एडवांस बनाना है। स्कूली शिक्षा के साथ-साथ आंगनवाड़ी सेंटरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी 2,148 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट लिया गया है। राज्य के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि राज्य में 50,000 आंगनवाड़ी सेंटरों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। इस मामले में भी, प्रोजेक्ट में एडीबी 70 फीसदी और राज्य सरकार 30 फीसदी हिस्सा लेगी। राज्य के फंड से 644.4 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से पांच साल में 50,000 आंगनवाड़ी सेंटर डेवलप होंगे। कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के 30 दिनों के अंदर काम शुरू हो जाएगा। चंद्रिमा ने कहा-यह प्रोजेक्ट आंगनवाड़ी सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने, बच्चों को अच्छी क्वालिटी का एजुकेशनल मटीरियल और न्यूट्रिशन देने और वर्कर्स की कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस करेगा।राज्य में 1,91,481 आंगनवाड़ी सेंटर हैं। जहां 2 लाख वर्कर्स और हेल्पर्स काम करते हैं। मंत्री ने कहा कि उनका 1,000 रुपये का मानदेय भी बढ़ाया गया है। हालांकि राज्य के सरकारी स्कूलों में अप्रैल से एग्जाम शुरू हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक राज्य में सेंट्रल फोर्स तैनात की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने इस बात पर गुस्सा जताया कि उनके लिए बड़ी संख्या में स्कूल बंद करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा-अगर केंद्र सरकार सोचती है कि स्कूल ही धर्मशाला हैं, तो केंद्र एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखता है, यह उनके नजरिए का सवाल है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली के डेवलपमेंट में राज्य सरकार की अहम भूमिका पर भी रोशनी डाली। नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा-इन 430 मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, लैब, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स के लिए खास सुविधाएं, बेहतर सैनिटेशन सुविधाएं और दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए खास पढ़ने की सुविधाएं होंगी।

राज्यसभा के लिए ममता ने 4 नामों पर लगाई मुहर

बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी और कोयल मल्लिक को बनाया उम्मीदवार

16 मार्च को होगा चुनाव

निज संवाददाता : राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होंगे। तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। राज्यसभा चुनावों के लिए बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार (पूर्व डीजीपी, पश्चिम बंगाल), मेनका गुरुस्वामी और कोयल मल्लिक को उम्मीदवार बनाया गया है।

बता दें कि बाबुल सुप्रियो फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और वह भाजपा से टीएमसी में शामिल हुए थे। अब ममता बनर्जी उन्हें राज्यसभा भेजेंगी। वह भाजपा सांसद रहते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं, पूर्व डीजीपी राजीव कुमार हाल में पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर हुए हैं और ममता बनर्जी ने पूर्व पुलिस अधिकारी को राज्यसभा भेजने का निर्णय किया है।

शारदा चिटफंड मामला हो या फिर सीबीआई की रेड का मामला हो, राजीव कुमार के साथ ममता बनर्जी सदा ही खड़ी रही हैं। कुछ दिन पहले राजीव कुमार ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उसी समय से, टीएमसी में राजीव कुमार के राज्यसभा में जाने के कयास लगने लगे थे। कई लोगों का कहना है कि एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मानहानि का केस करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति की जरूरत होती है। कई लोगों का मानना है कि राजीव कुमार को राज्य सरकार और सत्ताधारी पार्टी को समर्थन मिला है। इसके अलावा, कोयल मल्लिक एक बांग्ला एक्ट्रेस हैं। बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अपनी पहचान है। टीएमसी ने अभिनेत्री को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने का निर्णय किया है। दूसरी ओर, मेनका गुरुस्वामी ने आई-पैक पर ईडी की रेड मामले में राज्य सरकार की वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील मेनका गुरुस्वामी का नामांकन सियासी रूप से काफी अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होंगे। देश के 10 राज्यों की कुल 37 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से पांच सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर तृणमूल कांग्रेस को चार और भाजपा को एक सीट मिलना तय है। टीएमसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम उन्हें दिल से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।

उम्मीद है कि वे तृणमूल की मजबूती की विरासत और हर भारतीय के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए उसके पक्के वादे को बनाए रखेंगे। राज्यसभा के लिए तृणमूल उम्मीदवार सूची में कई नामों पर चर्चा हो रही थी। टीएमसी ने ऋतब्रत बनर्जी को राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया है। कहा जा रहा है कि वे इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। उनकी जगह कौन कैंडिडेट होगा, मौसम बेनजीर नूर की जगह कौन कैंडिडेट होगा, इस बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही थीं। शुक्रवार सुबह तृणमूल के अंदरूनी सूत्रों से खबर आई कि सुब्रत बख्शी एक बार फिर कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया।

विधानसभा चुनाव से पहले 28 सड़कों की होगी मरम्मत

कोलकाता नगर निगम ने दी मंजूरी

निज संवाददाता : विधानसभा चुनाव से पहले, कोलकाता नगर निगम शहर की सड़कों से जुड़ी जनता की सभी शिकायतों को दूर करने के लिए काम कर रहा है। हाल ही में मेयर काउंसिल की मीटिंग में कुल 28 सड़कों की मरम्मत को मंज़ूरी दी गई। नगर निगम प्रशासन के इस फ़ैसले से राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में शहर के 144 वार्डों में से 44 से ज़्यादा वार्डों में विपक्षी राजनीतिक दल आगे आए थे। कुछ चुनाव विश्लेषक के मुताबिक, नगर निगम की सेवाओं से नाराज़गी ने शहर के वोटरों के एक हिस्से को विपक्ष की तरफ़ धकेल दिया। इस संदर्भ में, नगर निगम विधानसभा चुनाव से पहले नागरिक सेवाओं की क्वालिटी सुधारने में सक्रिय रहा है। हालांकि, अधिकारियों का दावा है कि सड़कों की मरम्मत का चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। सड़कों की खराब हालत को लेकर कई इलाकों में लंबे समय से गुस्सा है। नगर निगम प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक, एक साथ कई सड़कों की मरम्मत का फ़ैसला उसी समस्या को हल करने के लिए लिया गया है। हालांकि, नगर निगम के सड़क विभाग के एक अधिकारी सड़क मरम्मत के मुद्दे को वोट से जोड़ने से हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर के अलग-अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर पानी के प्रोजेक्ट की पाइपलाइन का काम किया गया है। इस वजह से, कई सड़कों के बड़े हिस्से खराब हो गए हैं। कई मामलों में, थोड़ी मरम्मत भी मुमकिन नहीं है, और लगभग पूरी सड़क को ही फिर से बनाना पड़ रहा है। नगर निगम प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक, नगर निगम के बोरो 7, 10, 11 और 13 के तहत कम से कम 25 सड़कों को पानी के प्रोजेक्ट की पाइपलाइन के कारण फिर से बनाना पड़ रहा है। बाकी तीन सड़कों की मरम्मत पथश्री और दूसरे प्रोजेक्ट्स के तहत की जाएगी। जादवपुर और टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्रों के बाघाजतिन, पटुली, कस्बा, ईएम बाईपास, हाल्टू, रामलाल बाजार, गरफा, बेहाला और ठाकुरपुकुर के अलग-अलग हिस्सों में सड़क का काम शुरू हो चुका है। कई जगहों पर खुदाई के बाद, सड़कें लंबे समय से गंदी और गड्ढों से भरी हुई हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक, शहर में करीब 135 किलोमीटर पाइपलाइन का काम पूरा होने के बाद करीब 70 नई सड़कें बनानी होंगी। इनमें से 25 अभी बन रही हैं। बाकी सड़कों पर धीरे-धीरे टेंडर निकालकर काम शुरू करने का प्लान है। लोगों के एक ग्रुप के मुताबिक, चुनाव पास होने की वजह से प्रशासन यह कदम उठा रहा है। हालांकि, नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से प्रशासनिक और बुनियादी ढांचा की जरूरतों के आधार पर लिया गया है।

15 सालों में बंगाल में घटी बेरोजगारी दर

निज संवाददाता : ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य के युवाओं के साथ खड़े होने के लिए जो नई युवसाथी स्कीम शुरू की है, उसके लिए ज़िले-ज़िले रजिस्ट्रेशन को जहां ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं विपक्ष की आलोचना और कटाक्ष के जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने आंकड़ों के साथ दावा किया है कि पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में बेरोज़गारी दर बीजेपी शासित कई राज्यों के मुकाबले कम हुई है। तृणमूल के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2011 में राज्य में बदलाव के बाद पिछले 15 सालों में बेरोज़गारी दर सिर्फ़ 3.6 फीसदी रही है। लेकिन बिहार, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे बीजेपी-एनडीए शासित राज्य बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी के अंधेरे में डूबे हुए हैं। उदाहरण के लिए, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा में बीजेपी सरकार के दस साल के दौरान बेरोजगारी दर क्रमशः 8.5 फीसदी, 8.5 फीसदी, 6.1 फीसदी और 6.2 फीसदी थी। छत्तीसगढ़ में, भाजपा के 20 साल के शासन के दौरान बेरोजगारी 7.8 फीसदी तक पहुंच गई है। बिहार, जिसने बार-बार खेमा बदला और अब भाजपा का है, वहां 20 साल में बेरोजगारी दर 7.7 फीसदी तक पहुंच गई है।

'गोविंदभोग' समेत तीन तरह के चावल को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

निज संवाददाता : यूनाइटेड नेशंस (यूएन) ने राज्य के तीन तरह के चावल को अंतरराष्ट्रीय पहचान दी है, जिसमें गोबिंदभोग भी शामिल है। पश्चिम बंगाल के जिलों में राज्य सरकार के खास प्रोजेक्ट माटिर सृष्टि (मिट्टी का निर्माण) को भी पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर यह खबर दी। यूनाइटेड नेशंस से पहचान मिलने पर उन्होंने खुशी जताई। उन्होंने यह पहचान ग्रामीण बंगाल के लोगों, खासकर पश्चिम बंगाल के किसानों को समर्पित की। ममता ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (एफएओ) ने पश्चिम बंगाल के खुशबूदार गोबिंदभोग, तुलाईपंजी और कनकचूर चावल को फूड कल्चर का हेरिटेज लेबल दिया है।

इसके अलावा, राज्य सरकार के इंटरडिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट माटिर सृष्टि को इंटरनेशनल पहचान मिली है। इस प्रोजेक्ट के जरिए पश्चिमी जिलों में बंजर जमीन पर फसल उगाने की तकनीक में महारत हासिल की गई है।

वोटर लिस्ट जारी....

(प्रथम पृष्ठ का शेषांश)

प्रपत्रों के वितरण के साथ शुरू हुई थी। निर्वाचन आयोग को राजनीतिक उथल-पुथल, दस्तावेज सत्यापन नियमों में संशोधन और कानूनी चुनौतियों के बीच इस प्रक्रिया को अस्थायी रूप से पूरा करने और अंतिम लेकिन अपूर्ण सूची प्रकाशित करने में 116 दिन लगे। **ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 58 लाख से अधिक वोटर के हटाये गये** मसौदा मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हुई थी। इसके अनुसार, मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ रह गयी। मसौदा मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को इस आधार पर गणना प्रपत्र वितरित किये गये थे कि उनके नाम अगस्त 2025 तक राज्य की मतदाता सूची में शामिल हैं। 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मृत्यु, प्रवास, नाम दोहराव या पता नहीं मिलने के कारण हटा दिये गये।दूसरे चरण में 1.36 करोड़ वोटर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की श्रेणी मेंदूसरे चरण में 1.67 करोड़ मतदाताओं पर विचार किया गया। इनमें से 1.36 करोड़ मतदाताओं के संबंध में 'तार्किक विसंगतियां' पायी गयीं और 31 लाख मतदाताओं की 'मैपिंग' (दस्तावेजों का मिलान) नहीं हुई थी। लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम अब भी जनगणना प्रपत्रों में 'तार्किक विसंगतियों' के आधार पर कानूनी कार्रवाई के अधीन हैं। बंगाल में एसआईआर 2002 के बाद से इस तरह का पहला राज्यव्यापी अभ्यास है।

एक नजर में : बंगाल में एसआईआर 4 नवंबर 2025 को जनगणना प्रपत्रों के वितरण के साथ शुरू हुई एसआईर की प्रक्रिया 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हुआ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

7.66 करोड़ वोटर थे पश्चिम बंगाल में दिसंबर 2025 से पहले 7.08 करोड़ वोटर रह गये पश्चिम बंगाल के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7.08 करोड़ वोटर्स को मतदाता सूची में 3 श्रेणियों में बांटा जायेगा

58 लाख से अधिक नाम हटा दिये गये वोटर लिस्ट से58 लाख लोगों को हटाये जाने की वजह

मृत्यु प्रवास

नाम दोहराव पहचान नहीं हो पाया वोटर का पता नहीं लगाया जा सका **दूसरे चरण में 1.67 करोड़ मामलों की हुई सुनवाई 1.36 करोड़ 'तार्किक विसंगतियों' यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामले 31 लाख की नहीं हो पायी मैपिंग** 60 लाख मतदाताओं के मामले अब भी विचाराधीन कहां से मिल सकती है मतदाता सूची

जिला और उप-मंडल कार्यालयों मतदान केंद्रों निर्वाचन आयोग की वेबसाइट।

बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले...

'सबुज साथी' प्रोजेक्ट के तहत 1.25 लाख छात्रों को मिलेगी साइकिल

निज संवाददाता : राज्य सरकार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 'सबुज साथी' प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 1.25 लाख छात्रों को साइकिल देगी। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, अगर सब ठीक रहा तो सबुजसाथी प्रोजेक्ट के तहत साइकिल बांटने का काम इस फरवरी के तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगा। नवान्न की इस पहल को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी काफी चर्चा हो रही है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर सबुज साथी प्रोजेक्ट 2015-16 शैक्षणिक वर्ष में शुरू किया गया था। पहले साल कक्षा 9 से 12 तक के करीब 40 लाख छात्रों को साइकिल दी गई थीं। बाद के सालों में नीति बदली और छात्रों को कक्षा 9 में पहुंचते ही यह सुविधा मिलने लगी। अभी करीब 9,000 स्कूल इस प्रोजेक्ट के तहत हैं।

पिछले साल राज्य में 12 लाख 34 हजार छात्रों को साइकिल दी गई थीं। प्राशसनिक सूत्रों का दावा है कि 2026 में यह संख्या बढ़कर 12 लाख 47 हज़ार हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस साल सबुज साथी स्कीम के तहत करीब 1.25 मिलियन स्टूडेंट्स को साइकिल मिलने वाली हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक 1.38 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस स्कीम का फ़ायदा मिल चुका है। राजनीतिक हलके के एक हिस्से के मुताबिक, चुनाव आयोग मार्च के पहले हफ़्ते में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल की घोषणा कर सकता है। उससे पहले, नवान्न राज्य सरकार की अलग-अलग लोगों से जुड़ी स्कीमों का फ़ायदा ज़मीनी लेवल तक पहुंचाना चाहता है। स्कूल एजुकेशन, माइनॉरिटी डेवलपमेंट, बैकवर्ड क्लास वेलफेयर और ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिलकर इस स्कीम को लागू करने पर काम कर रहे हैं। हालांकि चुनाव से ठीक पहले साइकिल बांटने को लेकर स्वाभाविक रूप से राजनीतिक तनाव है, लेकिन सरकार का दावा है कि इस स्कीम का मुख्य मकसद छात्रों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना और ड्रॉपआउट कम करना है।

एसएसकेएम अस्पताल की अनूठी पहल

वार्ड में ही हो रही है कैंसर पीड़ित बच्चों की पढ़ाई

निज संवाददाता : पांचवीं क्लास का अर्नव सेनापति कैंसर से पीड़ित है। उसका इलाज एसएसकेएम में चल रहा है। अचानक जानलेवा बीमारी की वजह से, स्कूल के दरवाज़े से वह बहुत दूर हो गया। लेकिन एसएसकेएम की अनूठी पहल से स्कूल की रोशनी अस्पताल के अंदर आ गई है। कैसे? एसएसकेएम के पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की नोडल ऑफिसर डॉ. कौशांबी कर ने बताया कि एसएसकेएम में कैंसर पीड़ित बच्चों के पढ़ने का इंतज़ाम किया गया है। टीचर हफ़्ते में तीन दिन वार्ड में आ रहे हैं। क्लास ले रहे हैं। होमवर्क दे रहे हैं। इलाज के साथ-साथ पढ़ाई भी ज़ोरों से चल रही है।

एसएसकेएम के डायरेक्टर डॉ. मणिमय बनर्जी ने कहा कि इलाज के दौरान बच्चों को कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वे मुख्य धारा से अलग हो गए हैं। यह पहल इसी सोच पर आधारित है। इस कोशिश में कैनकिड्स नाम की संस्था साथ है। बच्चों का कैंसर धीरे-धीरे फैल रहा है। अकेले एसएसकेएम के पीडियाट्रिक हीमेटो-ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ही तीन साल में 168 बच्चों में ब्लड कैंसर का पता चला है। लेकिन, अगर कैंसर का पता कम उम्र में ही पहले स्टेज में चल जाए, तो इसे जल्दी ठीक किया जा सकता है। इसका सबूत एसएसकेएम का नया हीमेटो-ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है। हाल ही में इसका ऑफिशियली उद्घाटन हुआ। इसमें खास बेड दिए गए हैं।

हालांकि, यह डिपार्टमेंट पिछले तीन साल से एसएसकेएम के पीडियाट्रिक सर्जरी और रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर चल रहा है।

डॉ. कौशांबी कर ने कहा-तब कोई खास वार्ड नहीं था। तीन साल में एसएसकेएम में ल्यूकेमिया से पीड़ित 168 बच्चे आए हैं। हर कोई ठीक होने की राह पर है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। नए हीमेटो-ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हफ्ते में दो बार ओपीडी चल रही है। मंगलवार और गुरुवार। सूत्रों के मुताबिक, 2023 और 2025 के बीच ओपीडी में कैंसर के मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। 168 ल्यूकेमिया मरीजों में से सबसे ज्यादा बच्चे तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया या एएलएल से पीड़ित हैं। यह कैंसर बच्चों में सबसे आम है। एसएसकेएम में बच्चों में कैंसर के इलाज के लिए कई एडवांस्ड टेस्ट भी शुरू किए गए हैं। इनमें फ्लो साइटोमेट्री, कैरियोटाइपिंग, एफआईएसएच टेस्ट शामिल हैं। यह एफआईएसएच टेस्ट क्या है? डॉक्टरों ने बताया कि यह एक तरह का जेनेटिक टेस्ट है जिससे यह देखा जा सकता है कि खून या बोन मैरो सेल्स में डीएनए में कोई असामान्य बदलाव तो नहीं है। कैनकिड्स और रोटरी जैसी संस्थाओं ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है ताकि ये एडवांस्ड टेस्ट फ्री में किए जा सकें। बच्चों में कैंसर के इलाज के साथ-साथ, नए वार्ड में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दी जाती है।

विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए तृणमूल भवन में लगाया गया बायोडॉटा बॉक्स

आवेदनों की लगी बाढ़

निज संवाददाता : बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख शायद मार्च की शुरुआत में घोषित की जाएगी। इस वजह से, समय बहुत कम है। उससे पहले, सत्ता विरोधी सभी खेमे ज़ोरदार तैयारी कर रहे हैं। खासकर, इस बात को लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है। उससे पहले, तृणमूल भवन में एक बायोडेटा बॉक्स लगाया गया है। अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार उस बॉक्स में अपना बायोडेटा जमा कर सकते हैं। यह बॉक्स तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के आदेश पर लगाया गया है। सवाल यह उठता है कि क्या यह बायोडेटा बॉक्स नए चेहरे खोजने के लिए लगाया गया है? हालांकि, इस बॉक्स के लगने के बाद से उम्मीदवार बनने के लिए एप्लीकेशन की बाढ़ आ गई है। आवेदकों में डॉक्टर और सोशल वर्कर भी शामिल हैं। यहां तक कि कई विधायक और मंत्रियों ने भी बायोडेटा देने में दिलचस्पी दिखाई है। पता चला है कि ड्रॉप बॉक्स लगने के बाद डॉक्टर मृणालकांति साहा ने बंगाल विधानसभा में तृणमूल उम्मीदवार बनने के लिए अपना बायोडाटा जमा किया। उन्होंने मदर टेरेसा के साथ लंबे समय तक काम किया। सामाजिक कार्यकर्ता इनामुल हक ने भी अपना आवेदन जमा किया। सबसे खास बात यह है कि कई पूर्व और वर्तमान विधायकों ने भी उम्मीदवार बनने के लिए बॉक्स में आवेदन करने में रुचि दिखाई है। लालगोला से पूर्व विधायक चांद मोहम्मद का नाम इस लिस्ट में है। मेमारी विधायक मधुसूदन भट्टाचार्य और मालदा के मंत्री ताजमुल हुसैन भी हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह आवेदन जमा करने के लिए तृणमूल भवन में ड्रॉप बॉक्स लगाया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले भी बायोडाटा बॉक्स लगाया गया था। विधानसभा चुनाव सामने हैं। उससे पहले उस परंपरा का पालन करते हुए इस बार तृणमूल भवन में ड्रॉप बॉक्स लगाया गया है।

हालांकि, हर बार सत्ताधारी पार्टी तृणमूल अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके चौंका देती है। इस बार भी यह चलन शुरू हो गया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कई राजनीतिक समीकरण बदले हैं। ऐसे में, इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या पार्टी एक बार फिर पुराने लोगों पर ही भरोसा करेगी या कैंडिडेट लिस्ट में नए चेहरे दिखेंगे। पता चला है कि तृणमूल नेता ममता बनर्जी और सुब्रत बख्शी ने यह ड्रॉप बॉक्स लगाने का ऑर्डर दिया था। उन्होंने जिला अध्यक्षों को भी इस बारे में बताने का ऑर्डर दिया था। तृणमूल भवन के पहले फ्लोर पर ड्रॉप बॉक्स लगाया गया। खबर है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के दिन ड्रॉप बॉक्स की चाबी खोली जाएगी।

धापा और गरिया ढलाई ब्रिज पर नए वॉटर प्रोजेक्ट

- पानी की कमी को दूर करने के लिए कोलकाता नगर निगम का कदम

निज संवाददाता : कोलकाता नगर निगम के आस-पास के इलाकों (दक्षिण और दक्षिण-पूर्व) में फ़िल्टर्ड पीने का पानी सप्लाई पक्का करने के लिए दो नए वॉटर प्रोजेक्ट पर काम तेज़ी से चल रहा है। धापा और गरिया ढलाई ब्रिज के पास मॉडर्न वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। नगर निगम अधिकारियों का लक्ष्य मार्च-अप्रैल तक इन दोनों प्रोजेक्ट से पानी सप्लाई शुरू करना है।

धापा में बन रहे प्लांट की रोज़ाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 मिलियन गैलन है। दूसरी ओर, गरिया ढलाई ब्रिज पर एक और प्लांट बन रहा है, जहां रोज़ाना 10 मिलियन गैलन फ़िल्टर्ड पीने का पानी बनेगा। नगर पालिका प्रशासन का दावा है कि अगर ये दोनों प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं, तो नगर निगम के आस-पास के इलाकों, जैसे टॉलीगंज, जादवपुर और ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास से सटे बड़े इलाके के लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। हालाँकि, वॉटर प्रोजेक्ट का बनना ही सब कुछ नहीं है। उस पानी को पहुँचाने के लिए एक बड़े पाइपलाइन नेटवर्क की ज़रूरत है। नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक, करीब 350 करोड़ टका की लागत से 91 हिस्सों में करीब 135 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। 46 किलोमीटर से ज़्यादा में पाइप बिछाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। पाइप बिछाने के लिए अलग-अलग इलाकों में सड़कें खोदनी पड़ी थीं। इस बार नगर निगम अधिकारियों ने उन सड़कों की मरम्मत और उन्हें फिर से बनाने का काम तेज़ी से शुरू कर दिया है।

अभी करीब 25 सड़कों की मरम्मत का काम ज़ोरों पर चल रहा है। नगर निगम प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम पूरा करने के लिए रफ़्तार बढ़ा दी गई है। नगर निगम को उम्मीद है कि अगर दोनों प्रोजेक्ट समय पर शुरू हो जाते हैं, तो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व कोलकाता में पानी का संकट काफी हद तक कम हो जाएगा।

शहर की लाइटिंग में कई चरणों में होगा बदलाव

टीसीएस ने स्मार्ट लाइटिंग के लिए नगर निगम के साथ किया करार

निज संवाददाता : कोलकाता नगर निगम ने कोलकाता शहर के लाइटिंग सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने स्मार्ट लाइटिंग लागू करने के लिए आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (टीसीएस) के साथ एक एग्रीमेंट किया है। नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक, शहर के अलग-अलग इलाकों में सस्ती एलईडी स्ट्रीटलाइट लगाई जाएंगी और एक टेक्नोलॉजी-बेस्ड स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (प्रौद्योगिकी-आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली) शुरू किया जाएगा। पुराने पारंपरिक सोडियम वेपर और दूसरी स्ट्रीटलाइट की जगह एलईडी फिक्स्चर कई स्टेज में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही, एक केंद्रीय नियंत्रण और निगरानी प्रणाली शुरू किया जाएगा, जिससे रियल-टाइम फॉल्ट डिटेक्शन (वास्तविक समय दोष का पता लगाना), बिजली की खपत की मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस ज़्यादा असरदार तरीके से हो सकेगा। नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा-टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ के साथ यह प्रोजेक्ट शहर की बिजली की लागत कम करने में मदद करेगा और टेक्नोलॉजी-बेस्ड मॉनिटरिंग के कारण मेंटेनेंस बेहतर और तेज़ होगा। उन्होंने आगे दावा किया कि लंबे समय में, इस पहल से कार्बन एमिशन में काफी कमी आएगी और ऑपरेशनल लागत कम होगी। यह प्रोजेक्ट कई स्टेज में लागू किया जाएगा। पहले फेज़ में शहर की ज़रूरी सड़कों, रिहायशी इलाकों और दूसरे पब्लिक एरिया को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी के लिए, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कालीघाट और अलीपुर इलाकों में शुरू किया जाएगा। इन दोनों इलाकों में शुरुआती सर्वे और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद, इसे पूरी तरह से लागू करने का काम शुरू होगा।

'स्मार्ट लाइटिंग' सिस्टम में सेंसर के ज़रिए ज़रूरत के हिसाब से लाइटिंग की ऑटोमैटिक शेड्यूलिंग, लाइटिंग को कम करना और बढ़ाना और एक इंटेलिजेंट अर्बन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ज़रिए सेंट्रल कंट्रोल होगा। नगर निगम के लाइटिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज अधिकारी ने कहा-यह टेक्नोलॉजी शहर के लाइटिंग मैनेजमेंट को एक बिल्कुल नया डायमेंशन देगी। नगर निगम ने कहा कि शुरुआती स्टडी पूरी होने के बाद प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय आवंटन और काम पूरा करने की समय-सीमा घोषित की जाएगी।

विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में लौटा 'सेटिंग' शब्द

सत्ताधारी टीएमसी व विपक्ष आमने-सामने

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल की राजनीति में सेटिंग ऐसा शब्द है, जो बहुत सुनने को मिलता है और यह शब्द रहस्य और आरोपदोनों का पर्याय बन चुका है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह शब्द एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में लौट आया है। प्रतिद्वंद्वी दलों के बीच गुप्त समझौते (सेटिंग) के आरोप लग रहे हैं। राज्य की सत्ताधारी टीएमसी, मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा और वाम मोर्चा सभी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बंगाल की राजनीति में अक्सर सीपीमूल (सीपीआईएम और तृणमूल), बिजेमूल (भाजपा और तृणमूल) और राम-बाम (भाजपा और वाम मोर्चा) जैसे शब्द सुनाई देते हैं। टीएमसी लंबे समय से राम-बाम की थ्योरी पेश करती रही है, जिसके अनुसार 2019 के बाद वाम दलों के वोट धीरे-धीरे भाजपा की ओर स्थानांतरित हुए, जिससे भाजपा को मजबूती मिली। वहीं सीपीआई(एम) दोनों प्रमुख दलों पर एक-दूसरे के अस्तित्व से लाभ उठाने का आरोप लगाती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जब भी चुनावी समीकरण बनते हैं, टीएमसी और वाम दलों के बीच रणनीतिक सहयोग दिखता है। चुनाव नजदीक आते ही यह बयानबाजी और तीखी हो गई है। शासन और विकास के मुद्दों से ध्यान हटकर कथित गुप्त गठबंधनों की चर्चा प्रमुख हो गई है।

टीएमसी नेता कुनाल घोष ने सेटिंग (गुप्त समझौते) के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो राजनीतिक रूप से चुनौती नहीं दे पाते, वही ऐसी बातें गढ़ते हैं।

राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का कहना है कि कई महत्वपूर्ण सीटों पर विपक्षी वोटों का बिखराव सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाता है। उनका आरोप है कि वाम दल और कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से टीएमसी को लाभ पहुंचाते रहे हैं।

सीपीआईएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने भाजपा और टीएमसी के बीच डर की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि जब राजनीति व्यक्ति केंद्रित हो जाती है, तो वैचारिक बहस की जगह अफवाहें ले लेती हैं।

निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी ने भी नई चर्चाओं को जन्म दिया है। इसने इन आशंकाओं को हवा दी है कि नए दल वोट समीकरण बदलने के लिए खड़े किए जा रहे हैं।

टीएमसी नेताओं का आरोप है कि उभरते छोटे दल भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वोट काटने का काम कर रहे हैं। इसी तरह आईएसएफ और एआईएमआईएम पर भी ऐसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन दलों ने आरोपों को खारिज किया है।

विश्लेषकों के अनुसार, बंगाल में सेटिंग की राजनीति नई नहीं है। 1967 में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के गठन और संयुक्त मोर्चा के दौरान भी गुप्त समझौतों के आरोप लगे थे।

वाम मोर्चा शासनकाल में टीएमसी ने कांग्रेस और सीपीआईएम की नजदीकी के आरोप लगाए थे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे आरोपों को ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। जांच में देरी, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई या राजनीतिक चुप्पीसब अटकलों को जन्म देती हैं।

बंगाल में सेटिंग अब महज चुनावी स्टंट नहीं है, बल्कि चुनावी हकीकत बन चुकी है, जिसे सभी दल सार्वजनिक रूप से नकारते हैं, लेकिन मतदाता उत्सुकता से सुनते हैं।

हल करो हीरो बनो का उत्तर

1.सूरज की विपरीत, 2.अनुप्रस्थ तरंग, 3.प्रोटिन संश्लेषण, 4.पित्त रस, अग्नाशयी रस, 5. व्हेल,

संपादकीय

पीएम मोदी की इज़राइल यात्रा

दो देशों के बीच एकजुटता और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का संदेश

बीते बुधवार को नेसेट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का बड़ा संदेश इज़राइल के साथ एकजुटता था। मोदी ने अपने श्रोताओं को याद दिलाया कि नई दिल्ली और यरुशलम के बीच इस एकजुटता की बुनियाद दोनों देशों के लिए आतंकवाद से होने वाले खतरे को आपसी तौर पर मानना है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2023 में इज़राइल पर हमास के क्रूर हमले का ज़िक्र किया, जिसमें लगभग 1,200 इज़राइली मारे गए थे। फिर दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत का दायरा बढ़ाने के लिए एक जैसी भावना ने रास्ता बनाया। गुरुवार को, भारत और इज़राइल ने इस तरह अपने रिश्ते को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया। कई एग्रीमेंट साइन किए गए, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड, एग्रीकल्चर, एनर्जी, साइबरस्पेस और डिजिटल पेमेंट जैसे एरिया में सहयोग बढ़ा। सैन्य सहयोग को और बढ़ाया गया है : सैन्य हार्डवेयर का संयुक्त उत्पादन और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर इस मामले में ज़रूरी हिस्से होंगे। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के असल में होने की भी बात हो रही है जो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भारत में जल्द ही सरकार-से-सरकार के बीच बैठक होने की उम्मीद है। मोदी और नेतन्याहू के बीच की गर्मजोशी और उनका साझा नज़रिया, इज़राइल के साथ भारत के रिश्तों के लिए सहारा साबित हुआ है। लेकिन भारत इज़राइल को फ़िलिस्तीन और पड़ोस के मुश्किल मुद्दों से अलग नहीं कर सकता। इस मामले में, गाज़ा के ख़िलाफ़ इज़राइल की बेहिसाब जवाबी कार्रवाई पर एक शब्द भी न कहने के मोदी के फ़ैसले ने लोगों को हैरान कर दिया है जिसमें अब तक 72,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मोदी का अपने प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल भारत की बारीक रायआतंकवाद के ख़िलाफ़ इज़राइल का समर्थन और गाज़ा और वेस्ट बैंक में उसके कामों की आलोचनाको सामने रखने से मना करना, फ़िलिस्तीन के प्रति नेतन्याहू के नज़रिए का छिपा हुआ समर्थन माना जाएगा। गाज़ा शांति योजना के लिए उनका समर्थन भी असलियत से ज़्यादा सिर्फ़ बयानबाज़ी तक ही सीमित था। इज़राइल के प्रति भारत के नज़रिए का असर सिर्फ़ भारत, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर अरब दुनिया और पश्चिम एशिया में नई दिल्ली के रिश्तों पर भी पड़ता है, जो अमेरिका और ईरान के बीच संभावित लड़ाई की आहट को देखते हुए खतरे में हैं। मोदी की सरकार अपने दूसरे भागीदारों को अलग-थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकती, भले ही वह इज़राइल को काफी कसकर गले लगा रही हो।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रकरण: यूपी की राजनीति में धर्म, सत्ता और जनभावनाओं के टकराव का प्रतीक

इतना तय है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज एफआईआर अब सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं रह गई है। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म, सत्ता और जनभावनाओं के टकराव का बड़ा प्रतीक बन चुकी है। आने वाले महीनों में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नए तथ्य सामने आएंगे, वैसे-वैसे इस विवाद का राजनीतिक तापमान और बढ़ेगा, और इसका असर सूबे की राजनीति पर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा।

अजय कुमार

प्रयागराज के झूंसी थाने में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ अदालत के आदेश पर दर्ज एफआईआर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर धर्म, कानून और सत्ता के चौराहे पर ला खड़ा किया है। मामला जितना कानूनी है, उससे कहीं ज्यादा उसका असर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दिख रहा है। आरोप बेहद गंभीर हैं, धाराएं सख्त हैं और समय ऐसा जब हर घटना को चुनावी गणित से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि यह प्रकरण तेजी से सूबे की राजनीति के केंद्र में आ गया है। एफआईआर में पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। यह कानून बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में देश का सबसे सख्त कानून माना जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में देशभर में करीब 54 हजार पॉक्सो मामले दर्ज हुए थे। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश से लगभग 7,500 मामले सामने आए, यानी कुल मामलों का करीब 14 प्रतिशत। इनमें से करीब 65 प्रतिशत मामलों में पीड़ित की उम्र 16 साल से कम थी। आंकड़े बताते हैं कि यूपी में हर दिन औसतन 20 से अधिक पॉक्सो मामले दर्ज होते हैं। ऐसे माहौल में किसी बड़े धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति पर इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज होना स्वाभाविक रूप से असाधारण घटना मानी जा रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सुनियोजित साजिश बताया है। उनका कहना है कि जिन घटनाओं का उल्लेख शिकायत में किया गया है, वे कथित तौर पर 15 से 20 साल पुरानी बताई जा रही हैं। सवाल यह उठता है कि इतने लंबे समय बाद मामला क्यों सामने आया। शंकराचार्य का दावा है कि उनके गुरुकुल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जांच एजेंसियां चाहें तो तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वह जांच से भागेंगे नहीं और कानून का सामना करेंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राजनीतिक मंशा साफ दिखाई दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस एफआईआर को सरकार की नीयत से जोड़ते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव का कहना है कि जो सरकार खुद को सनातन धर्म की रक्षक बताती है, वही आज धर्म के सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक पर बैठे शंकराचार्य को झूठे आरोपों में घसीट रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदेश यात्राओं का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब प्रदेश में इतना संवेदनशील मामला सामने आया है, तब सरकार की प्राथमिकता क्या है।

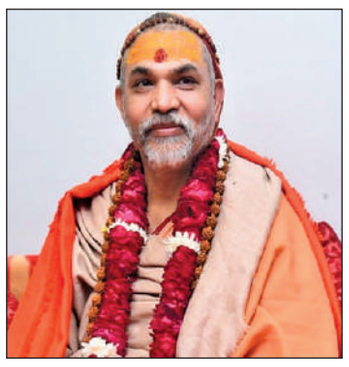

अखिलेश यादव ने इस विवाद को केवल धार्मिक या कानूनी मुद्दा मानने से इनकार किया। उन्होंने इसे पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों से समाज के बड़े हिस्से में नाराजगी बढ़ रही है। सपा के आंतरिक सर्वे के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में यूपी के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर करीब 12 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत के आसपास है। महंगाई के मोर्चे पर भी स्थिति चिंताजनक है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में पिछले तीन साल में औसतन 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सपा का तर्क है कि जब जनता पहले से इन समस्याओं से जूझ रही है, तब ऐसे विवाद सरकार के खिलाफ माहौल को और तेज कर रहे हैं। सरकार और उसके समर्थक इस पूरे मामले को कानून के राज से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि एफआईआर अदालत के आदेश पर दर्ज हुई है और पुलिस केवल न्यायिक निर्देशों का पालन कर रही है। भाजपा समर्थकों का तर्क है कि कानून सबके लिए समान है और धार्मिक पद या सामाजिक हैसियत किसी को कानून से ऊपर नहीं रख सकती। हालांकि यह भी सच है कि सरकार की ओर से अब तक कोई विस्तृत राजनीतिक बयान सामने नहीं आया है, जिसे विपक्ष अपने पक्ष में भुना रहा है। धार्मिक और सामाजिक स्तर पर भी यह मामला गहरे असर छोड़ रहा है। संत समाज का एक वर्ग शंकराचार्य के समर्थन में सामने आया है और इसे सनातन परंपरा पर हमला बता रहा है। उनका कहना है कि ऐसे आरोपों से न सिर्फ एक व्यक्ति, बल्कि पूरी संत परंपरा की छवि धूमिल होती है। वहीं कुछ धार्मिक संगठनों का मत है कि आरोप गंभीर हैं और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आंकड़ों के अनुसार, यूपी में दर्ज पॉक्सो मामलों में करीब 9 से 10 प्रतिशत मामलों में आरोपी सामाजिक रूप से प्रभावशाली या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े पाए गए हैं, जिससे ऐसे मामलों में विवाद और राजनीतिक दबाव बढ़ जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित मुद्दे हमेशा चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव दूर नहीं है, ऐसे विवादों का असर धीरे-धीरे जमीन पर दिखने लगेगा।

सपा इसे सत्ता की कथित दमनकारी नीति और संतों के अपमान के रूप में पेश कर रही है, जबकि भाजपा इसे न्यायिक प्रक्रिया बताकर अपने ऊपर लगे राजनीतिक आरोपों से बचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जांच शुरुआती दौर में है और कानूनी प्रक्रिया को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। लेकिन इतना तय है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज एफआईआर अब सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं रह गई है। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म, सत्ता और जनभावनाओं के टकराव का बड़ा प्रतीक बन चुकी है। आने वाले महीनों में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नए तथ्य सामने आएंगे, वैसे-वैसे इस विवाद का राजनीतिक तापमान और बढ़ेगा, और इसका असर सूबे की राजनीति पर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा।

जानें अपना राशिफल

मेष

किसी के काम से प्रभावित होकर काम करने वाला समय हो सकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, किसी के साथ मिलकर काम करने पर चर्चा हो सकती है जो फायदेमंद होगी।

वृषभ

समस्या का समाधान निकलने वाला समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करें, अपनी बुद्धिमानी से काम करने की जरूरत है, मन स्थिर रखें।

मिथुन

सुरक्षित समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई विदेश में व्यापार करने पर सहमति बन सकती है जो फायदेमंद होगी, मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क

गलतफहमी भरा समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं किसी से राय लेकर ही करे, कोई परिवार का सदस्य आपका समय खराब कर सकता है, मन स्थिर रखे।

सिंह

रणनीति बनाकर काम करने वाला समय हो सकता है, कोई बड़ा काम हाथ से निकल सकता है सावधानी रखे, किसी के बहकावे में आने से बचने की आवश्यकता है, मन चंचल रहेगा।

कन्या

तनाव भरा समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, प्रयास करने से कोई बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है, मन वश में रखें।

तुला

सशक्त समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, अपनी सोच सकारात्मक रखने की आवश्यकता है, मन स्थिर रखें।

वृश्चिक

मार्गदर्शन वाला समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करे, किसी अन्य व्यक्ति से काम करने पर बात बन सकती है, मन प्रसन्न रहेगा।

धनु

गुमराह करने वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई मित्र आपका समय खराब कर सकता है सावधान रहे, आपसी प्रेम बनाये रखे, मन शान्त रखें।

मकर

हैसियत दिखाने वाला समय हो सकता है, कोई वाहन खरिदने का विचार हो सकता है, किसी परिवार के सदस्य से मतभेद भी हो सकता है सावधान रहे, मन स्थिर रखें।

कुंभ

प्रेरणा लेकर काम करने वाला समय हो सकता है, कोई बहुत बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है, किसी नये व्यक्ति से काम आगे बढ़ सकता है, आपसी प्रेम बनाये रखे, मन चंचल रहेगा।

मीन

समझौता करके काम करने वाला समय हो सकता है, कोई रुका हुआ जमीन का काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करे, मित्र पुरा साथ दे सकते हैं, मन शान्त रखे।

एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से सम्बन्ध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा की रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे जो अब अपना काम ख़त्म कर घर वापस जाने की तयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा उसने शिक्षक से कहा, '' गुरु जी क्यों न हम ये जूते कहीं छिपा कर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं, जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा!!'' शिक्षक गंभीरता से बोले,'' किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें की इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है!!'' शिष्य ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम ख़त्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ, उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा की अन्दर कुछ सिक्के पड़े थे, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट-पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर-उधर देखने लगा, दूर-दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमे भी सिक्के पड़े थे मजदूर भावविभोर हो गया, उसकी आँखों में आंसू आ गए, उसने हाथ जोड़ ऊपर देखते हुए कहा ''हे भगवान्, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख-लाख धन्यवाद, उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखें बच्चों को रोटी मिल सकेगी।''मजदूर की बातें सुन शिष्य की आँखें भर आयीं। शिक्षक ने शिष्य से कहा ''क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्का डालने से तुम्हे कम ख़ुशी मिली?''शिष्य बोला,'' आपने आज मुझे जो पाठ पढाया है, उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है। देना देवत्त है।'' दोस्तों, सचमुच 'जाय ऑफ गीभींग' से बढ़कर और कोई सुख नहीं है! हमें इस कहानी से शिक्षा लेते हुए अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूर कुछ न कुछ दान देना चाहिए और ज़रुरत मंदों की हर संभव मदद करनी चाहिए!

एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था परी, वो बात-बात पर गुस्सा होती थी। उसकी मां उसे हमेशा समझाती रहती कि परी बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन परी अपना होमवर्क करने में व्यस्त थी। उसकी टेबल पर एक सुंदर-सा फूलों से सजा पॉट रखा था। तभी उसके छोटे भाई का हाथ उस पॉट से टकराया और गिरने पर उसके कई टुकड़े हो गए। अब क्या, परी गुस्से से बौखला उठी। तभी वहां उसकी मां ने एक आईना लाकर उसके सामने रख दिया। अब गुस्से से भरी परी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो कि गुस्से में बहुत ही बुरी लग रही थी। अपना ऐसा बिगड़ा चेहरा देखते ही परी का गुस्सा छू-मंतर हो गया। तब उसकी मां ने कहा, देखा परी! गुस्से में तुम्हारी शक्ल आईने में कितनी बुरी लगती है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अब परी को पता चल गया था कि गुस्सा करना कितना बुरा होता है। तभी से उसने गुस्सा न करने का एक वादा अपने आप से किया।

हल करो हीरो बनो

1. बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देता है।
(क) सूरज की ओर (ख) सूरज की विपरीत
(ग) समकोण पर (घ) सूरज के अभाव में
2. प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है।
(क) अनुप्रस्थ तरंग (ख) अनुदैर्ध्य तरंग
(ग) क और ख दोनों (घ) कोई नहीं
3. राईबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है।
(क) प्रोटिन संश्लेषण (ख) श्वसन
(ग) वसा संश्लेषण (घ) प्रकाश संश्लेषण
4. आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका में निभाता है।
(क) अग्नाशयी रस, लार (ख) लार, हाईड्रोक्लोरिक अम्ल
(ग) हाईड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेम (घ) पित्त रस, अग्नाशयी रस
5. निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते है।
(क) ऑक्टोपस (ख) स्किड
(ग) क्लाउन फिस (घ) व्हेल

(उत्तर इसी अंक में)

मार लो मुस्की

रिंकी टिंकू से- क्या कर रहे हो?
टिंकू - मच्छर मार रहा हूं.
रिंकी - अब तक कितने मारे?
टिंकू- 5 मारे, 3 फीमेल और 2 मेल.
रिंकी - कैसे पता चला कि मेल कौन है और फीमेल कौन?
टिंकू - तीन आईने पर बैठे थे और दो बियर के पास.

⏩⏩⏩⏩⏩

टीचर: बिजली कहां से आती है?
टीटू : सर मामाजी के यहां से
टीचर: वो कैसे
टीटू : जब भी बिजली जाती है पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली काट दी

⏩⏩⏩⏩⏩

I LOVE YOU वाला लैटर पड़ोसी के घर में डाल कर आयी हूं, अब वो जाने और उसकी वाइफ जाने, सुबह टमाटर नहीं दिया था ना डायन ने, अब भुगतो!

⏩⏩⏩⏩⏩

पत्नी : बाजार से दूध का एक पैकेट ले आओ! हां, अगर बाजार में नींबू दिखे तो छह ले आना।
पति छह पैकट दूध ले आया।
पत्नी : छह पैकेट दूध?
पति : हां छह पैकेट ही लाया हूँ। क्योंकि बाजार में नींबू दिख गए थे !!!

⏩⏩⏩⏩⏩

डॉक्टर - ताई तुझे ऐसी दवाई दूंगा कि तू फिर से जवान हो जाएगी।
ताई - न बेटा, ऐसा जुल्म न करिओ, मेरी पेन्शन बंध हो जाएगी

⏩⏩⏩⏩⏩

मास्टर जी- तुमने कभी कोई नेक काम किया है?
पप्पू- हां सर, किया है !
मास्टर- कौन सा?
पप्पू- एक बार एक लड़की आराम से घर जा रही थी, मैंने उनके पीछे कुत्ता लगा दिया, जल्दी घर पहुंच गई।

⏩⏩⏩⏩⏩

दो लड़कियां बस में सीट पर बैठने के लिए लड़ रही थीं.
कंडक्टर- अरे क्यों लड़ रही हो, जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाए, फिर क्या था, पूरे रास्ते दोनों शांति से खड़ी ही रहीं.

⏩⏩⏩⏩⏩

टीचर गोलू से - पांच में से पांच घटाने पर कितने बचेंगे?
गोलू - पता नहीं मैडम।
टीचर - अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं, और 5 भटूरे तुझसे मैं ले लूं, तो तेरे पास क्या बचेगा?
गोलू - छोले।

⏩⏩⏩⏩⏩

जज- क्या सबूत है कि एक्सीडेंट के समय तुम कार तेज़ नहीं चला रहे थे?
कार चालक- साहब, मैं अपनी पत्नी को लेने उसके मायके जा रहा था...
जज- और कहने की ज़रूरत नहीं। इतना सबूत काफ़ी है साबित करने को तुम कार तेज़ नहीं चला रहे थे।

⏩⏩⏩⏩⏩

टीचर ने फंटू से पूछा: 1869 में क्या हुआ?
फेटू: गांधीजी का जन्म
टीचरः बिलकुल सही... बैठ जा
टीचरः पप्पू तू बोल..... 1872 में क्या हुआ...?
पप्पू: गांधीजी तीन साल के हो गए..... मैं भी बैठू क्या?
टीचरः बाहर निकल।

⏩⏩⏩⏩⏩

लड़का - आई लव यू डियर.
लड़की - तुझे मेरी चप्पल का साइज तो पता है ना?
लड़का - अरे यार... तुमने तो पहले से ही गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए, भाड़ में जाओ मैं नहीं दे रहा कोई सैंडल-बैंडल...

⏩⏩⏩⏩⏩

माँ : बेटा क्या कर रहे हो
बेटा : पढ रहा हु माँ
माँ : शाबास! क्या पढ रहे हो
बेटा: आपकी होने वाली बहु के SMS, दे थप्पड़ दे थप्पड़

माथापच्ची–21

					1		5	
8				2		3		
7	4	6			8	2		1
9	3	4				1		
		8				4	2	9
2		5	3			8	1	7
		9		6				4
	8		1					

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक है, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी एवं खड़ी पंक्ति में एवं 3X3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

उत्तर अगले अंक में

माथापच्ची 20 का हल

1	8	4	2	9	7	5	6	3
5	7	6	3	1	4	9	2	8
9	3	2	6	8	5	4	7	1
7	4	5	9	3	1	2	8	6
8	6	3	5	4	2	1	9	7
2	1	9	8	7	6	3	4	5
4	2	7	1	6	3	8	5	9
3	5	8	7	2	9	6	1	4
6	9	1	4	5	8	7	3	2

अब मैथिली भाषा में भी होगी केमिस्ट्री की पढ़ाई

भारत सरकार और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने मिलाया हाथ

निज संवाददाता : विज्ञान और गणित जैसे विषय को आमतौर पर सबसे कठिन विषय माना जाता रहा है। खासकर उनकी तकनीकी शब्दावली के कारण इन्हें ज्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है। वहीं लंबे समय से यह धारणा रही है कि अगर किसी भी विषय को मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो उसे समझना आसान होता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब केमिस्ट्री को मैथिली भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। दरअसल, भारत सरकार के कमिशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सहयोग से केमिस्ट्री की मूलभूत शब्दावली मैथिली में तैयार और प्रकाशित की है। यह पहले नई शिक्षा नीति 2020 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा दिलाना है।

3500 से ज्यादा शब्दों का किया गया अनुवाद

इस योजना के तहत केमिस्ट्री के करीब 3500 से ज्यादा तकनीकी शब्दों का मैथिली में अनुवाद किया गया है। इन शब्दों के उपलब्ध होने के बाद 12वीं तक की केमिस्ट्री की किताबों को मैथिली में तैयार करना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि इससे मिथिलांचल के छात्रों को साइंस सब्जेक्ट समझने में बड़ी राहत मिलेगी। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसी दिशा में यह शब्दावली एक जरूरी कदम मानी जा रही है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय की योजना ऐसे ही आगे दूसरे सब्जेक्ट की किताबों को भी मैथिली में उपलब्ध कराना है। बताया जा रहा है कि इस शब्दावली का सीधा फायदा स्कूल स्तर के छात्रों को मिलेगा। खासकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को इसका ज्यादा फायदा होगा। तकनीकी शब्दों की उपलब्धता से केमिस्ट्री की किताबों का अनुवाद और पढ़ाई दोनों आसान होंगे। वहीं रिपोर्ट के अनुसार फ्यूचर में राजनीतिक शास्त्र और पत्रकारिता जैसे सब्जेक्ट की शब्दावली मैथिली में तैयार की जा रही है। साथ ही अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर भी इसी तरह का काम जारी है। वहीं यह शब्दावली तैयारी करने के लिए एक विशेष एक एक्सपर्ट समिति गठित की गई है। इसमें केमिस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ हिंदी, मैथिली और इंग्लिश भाषा के एक्सपर्ट भी शामिल थे। समिति में कई एकेडमिक और प्रोफेसर ने भी योगदान दिया है।

'इंडस्ट्री' की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट फिर करेगा व्यापक समीक्षा

ऐतिहासिक पीठ के करीब 50 साल पहले दिए फैसले पर किया जाएगा पुनर्विचार

निज संवाददाता : देश के श्रम कानूनों में प्रयुक्त शब्द 'इंडस्ट्री' की परिभाषा को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में व्यापक कानूनी समीक्षा होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया है कि इस पर विचार के लिए नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की जाएगी। यह पीठ औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और उससे पहले लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत 'इंडस्ट्री' शब्द के दायरे को स्पष्ट करेगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपिन एम पंचौली शामिल थे उन्होंने बताया कि बड़ी पीठ 17 मार्च से इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी और संभावना है कि बहस अगले दिन तक पूरी कर ली जाएगी। इस संदर्भ में सात न्यायाधीशों की एक ऐतिहासिक पीठ द्वारा करीब 50 साल पहले दिए गए फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। 1975 में न्यायमूर्ति वी आर कृष्णान

अय्यर ने एक अहम फैसले में 'इंडस्ट्री' की पहचान के लिए जो कानूनी कसौटी तय की थी, उसे अब दोबारा परखा जाएगा। खासतौर पर उस फैसले के पैरा 140 से 144 में निर्धारित सिद्धांतों की वैधता और व्याख्या पर संविधान पीठ विचार करेगी। 1975 के फैसले में अदालत ने 'ट्रिपल टेस्ट' का सिद्धांत विकसित किया था। इसके अनुसार कोई भी संस्था या प्रतिष्ठान तभी 'इंडस्ट्री' माना जाएगा जब वहां नियमित और व्यवस्थित गतिविधियां संचालित होती हों, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संगठित सहयोग मौजूद हो, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन अथवा वितरण इस उद्देश्य से किया जा रहा हो कि मानव की जरूरतों या इच्छाओं की पूर्ति हो सके। इस व्यापक व्याख्या के कारण क्लब, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सेवा आधारित संस्थाएं भी श्रम कानूनों के दायरे में आ गई थीं। अब यह देखा जाएगा कि क्या यह व्याख्या वर्तमान कानूनी और सामाजिक संदर्भ में उपयुक्त है या नहीं।

मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि क्या सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं या सार्वजनिक संस्थाओं की सामाजिक सेवाएं श्रम कानूनों के तहत औद्योगिक गतिविधि मानी जा सकती हैं। अदालत यह भी तय करेगी कि राज्य के कौन से कार्य ऐसे हैं जो औद्योगिक विवाद के दायरे से बाहर रखे जा सकते हैं। अदालत ने बताया कि इस मामले में पर्याप्त केस मैनेजमेंट पहले ही हो चुका है। पक्षकारों को 28 फरवरी 2026 तक अपने अतिरिक्त या अद्यतन लिखित तर्क दाखिल करने की अनुमति दी गई है। दोनों पक्षों के नोडल वकीलों को याचिकाओं, दस्तावेजों और साक्ष्यों का नया संकलन तैयार करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें रखने के लिए तीन घंटे का समय दिया गया है, जबकि प्रत्युत्तर के लिए एक अतिरिक्त घंटा तय किया है।

मरे हुए आदमी की हड्डी को युवक के पैर में किया गया ट्रांसप्लांट

निज संवाददाता : एक मरे हुए आदमी की हड्डी को एक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए युवक के पैर में ट्रांसप्लांट किया गया। यह हड्डी आरजी कर मेडिकल कॉलेज ने ट्रांसप्लांट की। डॉक्टरों ने बताया कि यह न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूर्वी भारत में भी इस तरह का पहला ट्रांसप्लांट है। मेडिकल भाषा में इसे एलोग्राफ्ट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। 17 फरवरी को सर्जरी के ज़रिए युवक के पैर में हड्डी ट्रांसप्लांट की गई। सरकारी मदद से इस प्रोसीजर का खर्च 2 लाख 40 हज़ार रुपये आया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड (एचओडी) संजय कुमार ने बताया कि सर्जरी अच्छी हुई। मरीज़ स्वस्थ है। हालांकि, मरीज़ को अभी भी ऑब्ज़र्वेशन में रखने की ज़रूरत है। यह भी देखना ज़रूरी है कि मरीज़ का शरीर इस प्रोसेस को कितना झेल सकता है। इसके साथ ही, हड्डी को ठीक होने में कितना समय लगेगा, यह भी एक ज़रूरी बात है। उत्तर 24 परगना के बीडा के रहने वाले पेशे से दिहाड़ी मज़दूर रिज़ाउद्दीन मंडल 2023 में एक दुर्घटना का शिकार हुए थे। एक लॉरी की टक्कर से उनकी जांघ की हड्डी का निचला हिस्सा कुचल गया था। उसके बाद उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसी साल मई में रिज़ाउद्दीन के पैर की सर्जरी हुई थी। जून में प्लास्टिक सर्जरी भी हुई थी। अगस्त में रिज़ाउद्दीन के पैर की एक और सर्जरी हुई थी। लेकिन उसके बाद भी स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। 2024 में ग्राफ्टिंग की गई। लेकिन उससे भी ज़्यादा मदद नहीं मिली। उस समय डॉक्टरों के पास सिर्फ़ एक ही रास्ता बचा था। एचओडी ने कहा कि मरीज़ की हालत देखने के बाद सबसे पहले यह तय किया गया कि मरीज़ को पहले बचाया जाए। कई सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की गईं। इन्फेक्शन भी ठीक हो गया। घाव सूख गया। इस बार दूसरा काम पैर की हड्डी पर था। क्योंकि वो पूरी तरह से कुचल गई थी। एचओडी ने कहा कि या तो पैर को घुटने से काटकर फिर से जोड़ना पड़ता। नहीं तो ट्यूमर प्रोस्थेसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता। नतीजतन, पैर छोटा हो जाता। फिर एलोग्राफ्ट के बारे में सोचा जाने लगा। अगर हड्डी का कोई हिस्सा खराब हो जाता है, तो ज़रूरत पड़ने पर इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। मरे हुए इंसान के शरीर से हड्डी लेकर उसे बदला जाता है। वीरा के युवक के मामले में भी ऐसा ही किया गया है। एचओडी संजय कुमार ने कहा-मरे हुए इंसान की हड्डी बदलना ही काफी नहीं है, यह भी देखना होता है कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सर्जरी डॉक्टर सुनीत कुमार हाजरा के नेतृत्व में की गई।

मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

'फ्री बिजली-पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी'

निज संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, तमिलनाडु बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहा है। वहीं एक मुकदमे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्यों में अपनाई गई मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा डालती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत समेत जजों ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा ज्यादातर राज्य पहले से ही घाटे में हैं, फिर भी विकास को छोड़कर मुफ्त सुविधाएं बांट रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा-जो लोग भुगतान नहीं कर सकते, उन्हें सहायता देना समझ में आता है। लेकिन अमीर-गरीब में फर्क किए बिना सबको मुफ्त देना गलत नीति है। इस दौरान कोर्ट ने चेतावनी दी और कहा अगर सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, साइकिल और बिजली मिलती रही तो लोगों में काम करने की भावना कम हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना

समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था।

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वे विकास को नजरअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं कोर्ट ने राज्यों को सलाह दी कि मुफ्त चीजें बांटने के बजाय, रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा, भारत में हम कैसी संस्कृति बना रहे हैं? क्या यह वोट पाने की नीति नहीं बन जाएगी? फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई में तय होगा कि ऐसे मुफ्त बिजली योजनाओं पर क्या नियम लागू होंगे। यह मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि कई राज्यों में चुनाव से पहले मुफ्त योजनाएं घोषित होती हैं और इससे सरकारी खर्च बढ़ता है, जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि गरीबों की मदद जरूरी है, लेकिन बिना सोच-समझ सबको मुफ्त सुविधाएं देना देश के विकास के लिए सही नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, हम भारत में कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं? यह समझ में आता है कि कल्याणकारी योजना के तहत आप उन लोगों को राहत दें जो बिजली का बिल नहीं चुका सकते। लेकिन जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं और जो नहीं हैं, उनके बीच कोई फर्क किए बिना मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टिकरण की नीति नहीं है?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कंपनी ने 2024 के विद्युत संशोधन नियमों के नियम 23 को चुनौती दी है। इसमें उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो-महीने में लगभग 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है, बिना किसी शर्त के यानी उपभोक्ता चाहे कितना भी खर्च करे, पहली 100 यूनिट के लिए बिल नहीं देना होता। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि बिजली दरों की घोषणा के बाद तमिलनाडु की कंपनी ने अचानक मुफ्त बिजली देने का फैसला क्यों किया।

दिल्ली समेत 22 राज्यों में जल्द शुरू होगा एसआईआर का तीसरा चरण

अप्रैल से होगा आगाज

निज संवाददाता : भारत निर्वाचन आयोग ने देश की मतदाता सूचियों को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तीसरे चरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। निर्वाचन आयोग ने शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की तैयारियों का जायजा लिया। आधिकारिक संकेतों के अनुसार, इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया का अगला चरण अप्रैल 2026 से शुरू होने की संभावना है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रारंभिक तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें ताकि मतदाता सूची से त्रुटियों को दूर कर एक शुद्ध डेटाबेस तैयार किया जा सके। मतदाता सूची शुद्धिकरण का यह सफर कई चरणों में विभाजित है। इस प्रक्रिया का पहला चरण विशेष रूप से बिहार में सफलतापूर्वक लागू किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणामों के बाद अक्टूबर 2025 में दूसरे चरण की शुरुआत की गई। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। इन दोनों शुरुआती चरणों के माध्यम से अब तक देश के लगभग 60 करोड़ मतदाताओं का डेटा कवर किया जा चुका है। वर्तमान में जिन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आयोग ने संपर्क साधा है, वहां लगभग 39 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। हालांकि, पिछले अनुभवों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि आयोग तीसरे चरण में इन सभी 22 क्षेत्रों को एक साथ शामिल करने के बजाय रणनीतिक रूप से कुछ राज्यों को अगले चरणों के लिए सुरक्षित रख सकता है। तीसरे चरण की इस सूची में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के साथ-साथ दिल्ली, लद्दाख और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। विशेष रूप से मणिपुर और उत्तराखंड जैसे राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त हो रहा है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूचियों से उन नामों को हटाना है जो अब मृत हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं या मतदान के लिए अयोग्य हैं। साथ ही, पात्र नए मतदाताओं, विशेषकर युवाओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनगणना 2027 के प्रस्तावित कार्यक्रम के साथ होने वाला संभावित टकराव है। जनगणना का हाउसलिस्टिंग यानी मकानों की सूची बनाने का कार्य इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच संपन्न होना है। दिल्ली, हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों ने पहले ही अपनी जनगणना संबंधी समय सीमा अधिसूचित कर दी है। चूंकि दोनों ही प्रक्रियाओं में जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए राज्यों को या तो जनगणना की तारीखों में संशोधन करना होगा या निर्वाचन आयोग से अनुरोध करना होगा कि उन्हें अगले चरण में रखा जाए। आगामी विधानसभा चुनावों और 2029 के आम चुनावों के मद्देनजर यह विशेष गहन पुनरीक्षण कूटनीतिक और प्रशासनिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और निर्वाचन आयोग जनगणना और मतदाता सूची पुनरीक्षण के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं। यदि प्रक्रियाओं में विस्तार दिया जाता है, तो तीसरे चरण का यह कार्य जून या जुलाई की शुरुआत तक खिंच सकता है। अंतत, इस पूरी कवायद का लक्ष्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव यानी मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन बनाना है।

इंदौर में एमआईबीएफ का विशेष बिजनेस ग्रोथ सत्र, सामुदायिक आर्थिक सशक्तिकरण पर रहा जोर

भोपाल/इंदौर : भारत के हृदय मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में माहेश्वरी इंटरनेशनल बिजनेस फाउंडेशन द्वारा ''बिजनेस मीटिंग एंड नेटवर्किंग ऑपर्च्युनिटी'' सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देशभर से नामचीन माहेश्वरी उद्योगपति, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉरपोरेट विशेषज्ञों और युवा उद्यमियों ने भाग लेकर नेटवर्किंग एवं सहयोग के नए अवसरों पर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के संस्थापक महामंत्री संतोष कुमार लाहोटी ने कहा कि एमआईबीएफ केवल नेटवर्किंग मंच नहीं, बल्कि माहेश्वरी समुदाय के लिए एक मजबूत व्यावसायिक इको-सिस्टम तैयार करने की दिशा में कार्यरत संगठन है। उन्होंने बताया कि संगठन सामूहिक विचार-विमर्श के माध्यम से नए अवसरों की आधारभूमि तैयार कर युवाओं और उद्यमियों को देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर तक विस्तार के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय एमआईबीएफ सामुदायिक आर्थिक उत्थान में लगातार योगदान दे रहा है। जयपुर, जोधपुर, मुंबई, उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत, नागपुर और कोलकाता में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने के बाद इंदौर में

आयोजित यह कार्यक्रम संगठन के बढ़ते विस्तार और ऊर्जा का प्रतीक है। वर्तमान में संस्था से 6000 से अधिक सदस्य जुड़े हैं। इनमें 3000 सीए, 1000 एमबीए, सीएस, एडवोकेट व अन्य प्रोफेशनल्स शामिल हैं, जबकि 2000 से अधिक देश-विदेश के प्रतिष्ठित उद्योगपति सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिलायंस समूह के उपाध्यक्ष मुकेश चेचानी ने कहा कि देश में माहेश्वरी समुदाय की जनसंख्या लगभग 8.5 लाख है और राष्ट्रीय जीडीपी में हिस्सेदारी 4 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने कहा कि समुदाय की बौद्धिक क्षमता और उद्यमशीलता की परंपरा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बल पर आज हम हर क्षेत्र में नई राह बना रहे हैं। वहीं, एमआईबीएफ के आगामी अध्यक्ष दीपक माहेश्वरी ने कहा कि व्यावसायिक नेटवर्किंग केवल परिचय का माध्यम नहीं, बल्कि प्रगति का सेतु है। संगठित प्रयास और पारस्परिक सहयोग से समाज आर्थिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इस अवसर पर आईसीएआई इंदौर के पूर्व चेयरमैन मौसम राठी, च्वाइस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के एसोसिएट डायरेक्टर विमल परवाल तथा एमएमयू की शोभा सदानी सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी सामुदायिक विकास, निवेश संभावनाओं और उभरते बाजारों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही कार्यक्रम में 20 महिलाओं को उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं, सभी ने आपसी समन्वय और साझा प्रयासों के माध्यम से व्यापारिक विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई।

केएमसी को पार्क स्ट्रीट ज़ोन के लिए 16 करोड़ रुपये का मिला सौदा

निज संवाददाता : एक आउटडोर एडवरटाइजिंग एजेंसी ने पार्क स्ट्रीट-कैमक स्ट्रीट-शेक्सपियर सारणी ज़ोन में होर्डिंग्स को मैनेज करने के लिए हर साल ₹16.38 करोड़ देने का ऑफर दिया है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केएमसी) ने वहां एडवरटाइजिंग राइट्स ई-ऑक्शन के लिए रखे हैं।मुंबई स्थित कंपनी साइनपोस्ट इंडिया लिमिटेड, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली कंपनी बनी है, के पास इन सड़कों पर लगे सभी मौजूदा होर्डिंग्स हटाने और उनकी जगह नए होर्डिंग्स लगाने का अधिकार होगा। बताए गए मकसदों में से एक है तीन सड़कों कोजो शायद कोलकाता के सबसे ज़्यादा दिखने वाले कमर्शियल इलाके हैं होर्डिंग्स से घिरी कुल जगह को कम करके साफ़ करना। केएमसी के एक अधिकारी ने कहा-अभी इन सड़कों पर 33,000 वर्गफुट होर्डिंग्स हैं। इसे घटाकर 18,000 वर्गफुट कर दिया जाएगा। नगर निगम के सूत्रों ने कहा कि यह पहली बार है जब कॉर्पोरेशन ने ई-ऑक्शन के ज़रिए शहर के किसी हिस्से के लिए एडवरटाइजिंग मैनेजमेंट के राइट्स ऑफर किए हैं। ऑक्शन पिछले साल पूरा हुआ था, और केएमसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट को फाइनल कर रहा है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। केएमसी के एक अधिकारी ने कहा-हमारे कई मकसद थे। हम सड़कों की सूरत बदलना चाहते थे, पुराने, खराब होर्डिंग्स को अच्छी तरह से डिजाइन किए गए स्ट्रक्चर से बदलना चाहते थे जो नया लुक दें। हम यह भी जानते थे कि सिविक बॉडी ई-टेंडर के बजाय ई-ऑक्शन से काफी ज्यादा रेवेन्यू कमाएगी। पार्क स्ट्रीट, कैमक स्ट्रीट और शेक्सपियर सरणी में शहर के कुछ सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रेस्टोरेंट, पब, रिटेल आउटलेट, शैक्षिक संस्था और कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। इसी के साथ यहां ब्रिटिश काल की राष्ट्रीय राजधानी के कॉलोनियल आर्किटेक्चर (औपनिवेशिक वास्तुकला) के कई उदाहरण हैं। ई-ऑक्शन फॉर्मेट के तहत, प्रतिभागी वास्तविक समय में पूरा करने वाली बोलियां देख सकते हैं और एक-दूसरे से ज्यादा बोलियां लगा सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा-इससे केएमसी को विज्ञापन अधिकार चाहने वालों से ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू पाने में मदद मिलती है। केएमसी पहले इन तीन सड़कों पर होर्डिंग्स से सालाना लगभग ₹5 करोड़ कमाती थी। ऑक्शन के बाद, सालाना रेवेन्यू ₹16 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने कहा-चुनी गई कंपनी को एलईडी पैनल या स्टैटिक होर्डिंग लगाने की इजाज़त होगी। अगर वे ज़्यादा एलईडी पैनल इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पैसे देने होंगे।

अब शादीशुदा बेटियों को भी मिलेगी ग्रेच्युटी

- राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नवान्न का बड़ा फैसला
- बदली गई परिवार की परिभाषा

निज संवाददाता : बंगाल में सरकारी नियमों में परिवार की परिभाषा में शादीशुदा और तलाकशुदा बेटियों को शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से इस मुद्दे पर कई मामलों में कानूनी तनाव पैदा होता था। अब, प्रशासनिक हलकों का मानना है कि वह कानूनी उलझन भी जल्दी हल हो जाएगी। सोमवार को वित्त विभाग की पेंशन ब्रांच ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए डेथ ग्रेच्युटी या मौत की वजह से मिलने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स (वित्तीय लाभ) के नियमों में बहुत अहम बदलाव किया गया है। इस बार शादीशुदा बेटियों को भी इसका फायदा मिलेगा।

सरकारी निर्देश में साफ कहा गया है कि, संविधान के आर्टिकल 309 की शक्ति के तहत, गवर्नर ने वेस्ट बंगाल सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट) रूल्स, 1971 के रूल 7 के कुछ सब-सेक्शन में बदलाव किया है। इस बदलाव का मुख्य मकसद डेथ ग्रेच्युटी के मामले में परिवार की परिभाषा को पाने वाले के तौर पर और बढ़ाना और मॉडर्न बनाना है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, डेथ ग्रेच्युटी पाने के लिए 'फ़ैमिली' की परिभाषा में अब शादीशुदा बेटियां भी शामिल कर ली गई हैं। अब से, 'फ़ैमिली' का मतलब होगा

1) मरे हुए पुरुष कर्मचारी की पत्नी
2) महिला कर्मचारी का पति
3) बेटे, जिसमें सौतेले बेटे भी शामिल हैं
4) बिना शादी की, विधवा और तलाकशुदा बेटियां (सौतेली बेटियों सहित)
5) 18 साल से कम उम्र के भाई, बिना शादी की या विधवा बहनें,
6) मरे हुए कर्मचारी के पिता
7) मरे हुए कर्मचारी की मां
8) शादीशुदा बेटियां।

अब से, 'परिवार' का मतलब ये होगा :

1) मरे हुए पुरुष कर्मचारी की पत्नी
2) महिला कर्मचारी का पति
3) बेटे, जिनमें सौतेले बेटे भी शामिल हैं
4) बिना शादी की, विधवा और तलाकशुदा बेटियां (सौतेली बेटियों सहित)
5) 18 साल से कम उम्र के भाई, बिना शादी की या विधवा बहनें
6) मरे हुए कर्मचारी के पिता
7) मरे हुए कर्मचारी की मां
8) शादीशुदा बेटियां

नोटिफिकेशन के आखिर में एक बहुत ज़रूरी नोट या स्पेशल नोट दिया गया है, जिससे कई परिवारों की लंबे समय से चली आ रही कानूनी उलझनों को सुलझाने में मदद मिलेगी। बताया गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत इस नए नियम के लागू होने से पहले हो गई है और उसकी तलाकशुदा या शादीशुदा बेटियों की ग्रेच्युटी से जुड़ा कोई एप्लीकेशन या क्लेम अभी भी पेंडिंग है, तो संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक उन 'मामलों' पर नए सिरे से विचार करके उन्हें सुलझा सकेगा।

नवान्न सूत्रों के मुताबिक, राज्य के सभी संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट (प्रशासनिक विभाग) को गाइडलाइंस को तुरंत लागू करने के लिए पहले ही बता दिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने कहा कि राज्य सरकार के इस दयालु फैसले से मृतक राज्य सरकार के कर्मचारियों की शादीशुदा और तलाकशुदा बेटियों को फायदा होगा।

डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स से हो सकती हैं दिमागी दिक्कतें

- ड्रग कंट्रोल बोर्ड ने दवा की स्ट्रिप पर अनिवार्य की चेतावनी

निज संवाददाता : कुछ एंटीबायोटिक्स लंबे समय तक लेने पर चिड़चिड़ापन और बेचैनी हो सकती है। एंग्जायटी से जुड़ी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन ने डॉक्सीसाइक्लिन पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। संगठन की तरफ से इस बारे में हर राज्य को एक नोटिस भेजा गया है। इसमें साफ कहा गया है कि डॉक्सीसाइक्लिन स्ट्रिप पर यह चेतावनी लिखना अनिवार्य होगा- डॉक्सीसाइक्लिन से बेचैनी, एंग्जायटी से जुड़ी दिमागी दिक्कतें हो सकती हैं। मूड चिड़चिड़ा हो सकता है। केंद्र के फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम में लंबी बातचीत के बाद एक्सपर्ट्स को इसके सबूत मिले हैं। डॉक्सीसाइक्लिन बनाने वाली सभी कंपनियों को अपने पैकेज पर यह चेतावनी लिखनी होगी। हालांकि डॉक्टरों ने खरीदारों को इस साइड इफ़ेक्ट से बेवजह घबराने की सलाह नहीं दी है। डॉक्सीसाइक्लिन पांच दशकों से डॉक्टरों की पसंदीदा दवा रही है। यह एंटीबायोटिक निमोनिया और स्क्रब टाइफस समेत कई बैक्टीरियल बीमारियों को ठीक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। डॉक्टर दवा के नए साइड इफ़ेक्ट को लेकर परेशान हैं। सूत्रों के मुताबिक, एंटीमाइक्रोबियल और एंटीपैरासिटिक ड्रग्स पर बनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी में भी डॉक्सीसाइक्लिन के इस साइड इफ़ेक्ट के मुद्दे पर चर्चा हुई है। एसएसकेएम हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉ. नीलाद्री सरकार ने कहा कि लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यह दवा बेकार है। ऐसे में मरीज़ को यह एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग में भर्ती ज़ोरों पर

विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में भारी रोज़गार

निज संवाददाता : राज्य स्वास्थ्य विभाग में भर्ती ज़ोरों पर है। फार्मासिस्ट से लेकर जीएनएम नर्सिंग,स्टाफ नर्स से लेकर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट तक, हर जगह एप्लीकेशन आ रहे हैं। कई पोस्ट के लिए भर्ती भी पूरी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के सर्कुलर के मुताबिक, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी या जीएनएम नर्सिंग के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 3,363 वैकेंसी निकाली गई थीं। वहां 40,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन जमा हुए थे।कंप्यूटर टेस्ट और इंटरव्यू के बाद आखिरकार पैनल की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट में कुल 416 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए हैं। हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में 47 अलग-अलग डिपार्टमेंट में करीब 522 वैकेंसी थीं। वहां असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए गए हैं। हर जिले में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए भी डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर या जीडीएमओ के पद के लिए 1,227 वैकेंसी थीं। लगभग आठ गुना ज़्यादा एप्लीकेशन जमा किए गए। 8,049 लोगों ने अप्लाई किया। जिसमें से 1,132 लोगों का पैनल पब्लिश हो चुका है। फार्मासिस्ट का पैनल भी बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है। बंगाल में मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के बीच भी खुशी का माहौल है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में पांच गुना ज़्यादा एप्लीकेशन जमा किए गए। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पद के लिए 807 वैकेंसी थीं। 4,297 एप्लीकेशन जमा किए गए। उनमें से 4,020 लोगों को कंप्यूटर टेस्ट के लिए चुना गया। कंप्यूटर टेस्ट के नतीजों के मुताबिक, 1,547 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू प्रोसेस जल्दी पूरा करके हर सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया जाएगा। नई नौकरी पाने वालों में 2,611 स्टाफ नर्स भी शामिल हैं।

1 मई से सभी इंपोर्टेड चाय की गुणवत्ता और सुरक्षा अनुपालन की होगी जांच

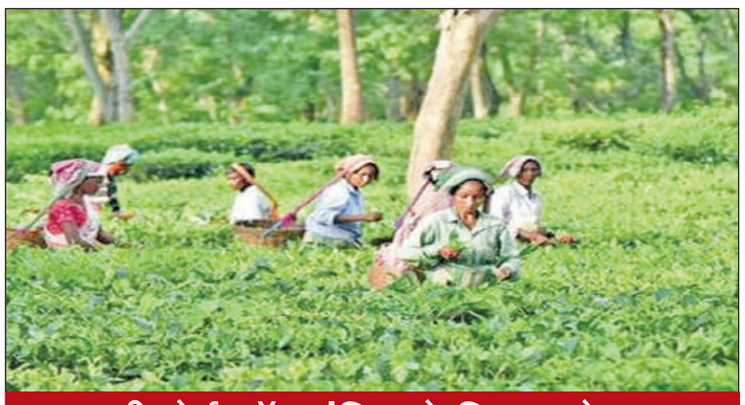

टी बोर्ड ऑफ़ इंडिया ने दिया आदेश

निज संवाददाता : टी बोर्ड ऑफ़ इंडिया ने आदेश दिया है कि 1 मई से सभी इंपोर्टेड चाय की क्वालिटी टेस्टिंग की जाएगी। टी बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन सी. मुरुगन ने 10 फरवरी के एक निर्देश में कहा-उक्त टी (डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट) कंट्रोल ऑर्डर, 2005 के पैराग्राफ 34 के तहत मिली पावर का इस्तेमाल करते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि, 1 मई 2026 से, चाय के सभी इंपोर्ट कंसाइनमेंट की क्वालिटी पक्का करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार, ज़रूरी तौर पर टेस्टिंग की जाएगी''2013 में, चाय इंपोर्ट के लिए एक ऑनलाइन ज़रूरी चेकिंग सिस्टम शुरू हुआ था, जिसके तहत बोर्ड चाय के सैंपल टेस्ट करता था और हर एप्लीकेंट को ऑनलाइन एक ''क्लियरेंस सर्टिफिकेट'' जारी किया जाता था। लेकिन, कॉमर्स पर एक विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने 12 अगस्त, 2025 की अपनी 194वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि बढ़ते इंपोर्ट और मिलावट के खतरों को देखते हुए, सख्त मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। भारत हर साल नेपाल और श्रीलंका समेत दूसरे देशों से 25 से 30 मिलियन किलो चाय आयात करता है। पहले, दार्जिलिंग टी एसोसिएशन ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि ''सस्ती और शक वाली नेपाली चाय को एफएसएसएआई चेक के बिना इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जा रही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (एफएसएसएआई) केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक कानूनी संस्था है, और यह दूसरी चीज़ों के अलावा, खाने की चीज़ों की क्वालिटी को रेगुलेट करती है। डीटीएके एक अधिकारी ने कहा-नेपाल से घटिया क्वालिटी और एपएसएसएआई का पालन न करने वाली चाय की सस्ती ड्यूटी-फ्री डंपिंग ने दार्जिलिंग चाय इंडस्ट्री को आईसीयू का मरीज़ बना दिया है। मई से, इंपोर्ट करने वालों को एक खास पोर्टल के ज़रिए शिपमेंट डिटेल्स, वेयरहाउस की जानकारी, कंटेनर नंबर और दूसरी डिटेल्स जमा करनी होंगी और इंपोर्ट से पहले एक प्रोविजनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। टी बोर्ड के अधिकारी पहुंचने पर, सुरक्षा अनुपालन की जांच के लिए मान्यता प्राप्त लैब में टेस्टिंग के लिए सैंपल लेंगे। इंपोर्ट की गई चाय को अलग से स्टोर किया जाना चाहिए और फाइनल क्लियरेंस मिलने तक उसे बेचा या दोबारा एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई सैंपल स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता है, तो इंपोर्टर रिज़र्व सैंपल टेस्टिंग के लिए कह सकता है। हालांकि, दोनों में से कोई भी फेल होने पर उसे टी (वेस्ट) कंट्रोल ऑर्डर, 1959 के तहत चाय के कचरे के तौर पर डिस्पोज़ कर दिया जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट की गई चाय को छह महीने के अंदर दोबारा एक्सपोर्ट करना होगा। भारतीय चाय के साथ ब्लेंड्स को पैकेजिंग और डॉक्यूमेंट्स पर साफ-साफ बताना होगा।दार्जिलिंग के एक चाय बागान मालिक ने कहा-अगर इसे अच्छी तरह से लागू किया जाता है तो इस कदम का स्वागत है।

छात्रा के सिर पर युवक ने जबरन सिंदूर लगाने का किया प्रयास, हुआ गिरफ्तार

झाड़ग्राम में दिखा अजीबो-गरीब नजारा

'मैं सच में डरी हुई हूं। झाड़ग्राम शहर से यूनिवर्सिटी तक सड़क के दोनों तरफ जंगल और कई खाली जगहें हैं। कोई बस्ती नहीं है। मैंने सुरक्षा के लिए प्रशासन को कई बार सूचित किया है। इस सड़क पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।'

-चंद्रदीपा घोष, वाइस-चांसलर, साधु रामचंद्र मुर्मू यूनिवर्सिटी

निज संवाददाता : परीक्षा के बाद पिता अपनी बेटी और उसकी सहेली को मोटरसाइकिल पर घर ले जा रहा था। तभी अचानक पीछे से एक और बाइक पास आ गई। पिता को डर लगा कि बाइक वाले उन्हें लूटने के लिए पीछा कर रहे हैं। इस पर छात्रा के पिता ने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी। पीछे वाली बाइक की स्पीड भी बढ़ गई। वह ठीक छात्रा के पिता की बाइक के पास आ गई। उन्होंने देखा कि पीछे से आ रही बाइक का ड्राइवर एक हाथ से बाइक का हैंडल पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से उनकी बेटी के सिर को पकड़ रहा है। लड़के के हाथ में सिंदूर का पैकेट था। पश्चिम बंगाल के व्यस्तम झाड़ग्राम-लोधाशुली रोड पर इस सीन के आगे शायद कोई भी फिल्म का सीन फीका पड़ जाए। कुछ फिल्मी स्टाइल में एक गांव के एक युवक ने उनकी दोनों बाइक रोक लीं। देखते ही देखते सड़क पर लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही बाइक रुकी, युवक ने फिर लड़की को पकड़ लिया और उसकी मांग में सिंदूर लगाने लगा।

लड़की के पिता ने उसे रोका। लड़की अपने पिता से गले मिली और फूट-फूट कर रोने लगी। झाड़ग्राम पुलिस स्टेशन ने युवक श्रीधर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि लड़की का घर पश्चिम मेदिनीपुर जिले में है। वह पढ़ाई के लिए झाड़ग्राम के एक मेस में पढ़ रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लड़की का पश्चिम मेदिनीपुर के पड़ोसी युवक से लंबे समय से प्रेम संबंध था। कुछ महीने पहले उनका रिश्ता टूट गया। लड़की ने रिश्ते से बाहर आकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। जब युवक ने शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसने मना कर दिया। लड़की ने कहा कि एक समय मेरा उसके साथ रिश्ता था। अब कुछ नहीं है। मैं पढ़ना चाहती हूं। लेकिन वह मुझे परेशान कर रहा है। आज उसने पीछे से मेरे बाल खींचकर मुझे सिंदूर लगाने की कोशिश की। अगर मुझे थोड़ी देर और होती तो मैं बाइक से गिर जाती। छात्रा के पिता ने शिकायत की और कहा कि लड़का कुछ दिनों से मेरी बेटी को परेशान कर रहा था। मैंने लड़के को कई बार चेतावनी दी है। मैं लड़के के डर से अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रहा हूं। मेरी बेटी की परीक्षा चल रही हैं। अगर वह चलती बाइक से गिर जाती, तो हम सब मर जाते। मुझे बताओ अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह परीक्षा कैसे देगी?इस पर मानिकपाड़ा बीट हाउस के विलेज पुलिस ऑफिसर रंजीत पाल ने कहा कि पीछे से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसे लूटने की कोशिश की जा रही थी। अगर उसे थोड़ी देर और होती तो बस के सामने दो बाइक गिर जातीं। उस बाइक पर छात्रा के पीछे उसकी एक दोस्त बैठी थी। उसके कपड़े पर भी सिंदूर से रंग लग गए थे। घटना के बारे में पता चलने पर वाइस-चांसलर चंद्रदीपा घोष ने साधु रामचंद मुर्मू यूनिवर्सिटी से एक टीम मौके पर भेजी।

उन्होंने कहा कि मैं सच में डरी हुई हूं। झाड़ग्राम शहर से यूनिवर्सिटी तक सड़क के दोनों तरफ जंगल और कई खाली जगहें हैं। कोई बस्ती नहीं है। मैंने सुरक्षा के लिए प्रशासन को कई बार सूचित किया है। इस सड़क पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। झाड़ग्राम पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल पर दो से ज्यादा लोगों का चलना मना है। मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनना जरूरी है। ऐसे में अगर लड़की के सिर पर हेलमेट होता, तो शायद युवक इस तरह सिंदूर लगाने की कोशिश नहीं करता। इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया।

ममता पर भारी धर्म की दीवार

- झारखंड से खोई मां 25 साल बाद बंगाल में मिली
- बेटे ने धर्म का हवाला देते हुए अपनाने से किया इनकार

मेरे पिता ने शादी के बाद क्रॉस पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन इससे वे ईसाई नहीं बन गए। अगर वह हिंदू धर्म में परिवर्तित नहीं होती है, तो घर में परेशानी होगी। मैंने उनसे कहा कि मैं हिंदू हूं और उन्हें अब धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। मेरे पिता और दादा हिंदू थे। उनके पिता ने भले ही एक ईसाई से शादी की हो, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं बदला।

-मदन बेसरा

निज संवाददाता : 25 साल बाद अपने परिवार से मिली महिला को उसके परिवार ने सिर्फ इसलिए अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि महिला ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। महिला के बेटे ने शर्त रखी कि अगर उसकी मां ईसाई धर्म छोड़कर, हिंदू धर्म अपना ले तो वे उसे अपना सकते हैं। दरअसल, यह बुजुर्ग महिला कोलकाता के एक आश्रय गृह में रह रही है। दो दशक पहले वह इस आश्रय गृह में आई थीं। कोलकाता के आश्रय गृह में इस बुजुर्ग महिला ने अपने जीवन के 25 साल बिताए। उसकी याददाश्त कमजोर हो गई। इस दौरान काउंसलिंग हुई। बुजुर्ग महिला का इलाज हुआ। महिला को अपने घर का पता याद आया। वह और आश्रय गृह में सब खुश थे कि आखिरकर बीस साल बाद अम्मा अपने घर जा सकेंगी। लेकिन सारी खुशियां तब हवा हो गईं, जब उनके बेटे ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। हैरानी की बात है कि उसने इसके लिए धर्म का हवाला दिया।

महिला का पता झारखंड के गोड्डा जिले के एक गांव का है। उनका बेटा मदन बेसरा दाहुपागर गांव के उसी घर में रहता है जहां से वह बीस साल पहले लापता हुई थीं। बुजुर्ग महिला की उम्र अभी 70 साल की है। उनकी नाम सुशीला मुर्मू है। वह अपने पति की मृत्यु के बाद लापता हो गई थीं। सुशीला के पति हिंदू धर्म के थे, जबकि सुशीला क्रिस्चन धर्म का पालन करती थीं। यह उसका धर्म ही था जिसने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पड़ोसियों ने उनके पति के निधन के बाद उन्हें हिंदू धर्म का पालन ही करने को कहा। वह ईसाई धर्म को मानती थीं और उन्होंने हिंदू धर्म का पालन करने से इनकार कर दिया। उनके परिवार और रिश्तेदारों ने भी उन्हें घर और गांव छोड़ने को कह दिया।

सुशीला मुर्मू को बहुत कम याद है कि वह कोलकाता कैसे पहुंची। उन्हें 2001 में मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी के एक सदस्य ने देखा और ले जाया गया। वह इसके एक आश्रय गृह में रहती थी। दशकों से, उसने आश्रय गृह को अपना घर मान लिया था, लेकिन कभी-कभी अपने परिवार को याद करती थी और अपने पति के बारे में बात करती थी।

आश्रय गृह के एक कर्मचारी ने महिला की आपबीती कोलकाता के एक शौकिया रेडियो ऑपरेटर को सुनाई। अंबरीश नाग विश्वास ने कहा कि हमने बुजुर्ग महिला की तस्वीर अपने नेटवर्क में प्रसारित की। उसकी कहानी बाहर आई तो उसके गांव का पता दाहुपागर गांव में चला।

मां और बेटे ने वीडियो कॉल पर बात की, कम से कम 25 साल बाद यह उनकी पहली बातचीत थी। सुशीला मुर्मू ने कहा कि उसने मुझसे कहा कि वह मुझे वापस नहीं ले सकता जब तक मैं अपना धर्म न बदल लूं। लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। यह मेरी उससे आखिरी बात थी। लीलाधा पंचायत के मुखिया, विकेश कुमार ने कहा कि दहुपागर मेरे गांव के पास है और मैं मदन बेसरा को जानता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी मां घर छोड़कर चली गई है।

वसंत को बदरंग करती आज की होली

रंगोत्सव पर विशेष

गोविन्द अग्रवाल

महादेव के काशी, कन्हैया के ब्रज और रघुवीर के अवध की पावन भूमि से चली होली यानी पवित्रता आज अपना अर्थ खो बैठी है। दिखावे और फ़ैशनपरस्ती की चकाचौंध में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को भूलने के कगार पर ला चुके हैं हम। यही वजह है, होली नाचता गीत, गाता अध्यात्म होते हुए भी आज की रस्मी होली अपनी पारंपरिक संस्कृति, आपसी भाईचारे और मर्यादा को पीछे छोड़ नशाखोरी, रंज़िश और बेशर्मी की ओर बढ़ने लगी है। ऐसा भी दौर गुज़रा है, जब वसंत के स्वागत में होली की आहट होते ही ठुमरी, कजरी, ख्याल, ध्रुपद, धमार के तर्ज़ पर फाग गीत कानों में रस घोलते थे। आज जब चलन ही नहीं रहा, तो झांझ-मंजीरे पर फगुआ की तान छेड़नेवाले भी कम ही रह गये हैं। अव्वल तो होली की मर्यादा ही दांव पर लगी हुई है।

देखते-ही-देखते बदल गये हैं होली के मायने!

मौजूदा वक़्त में अबीर-गुलाल और मिठाई के साथ अपनों से मिलने का मजा ही किरकिरा ही कर रखा है होली का बदला मिजाज! ज़िंदगी में रंग भरने का पैग़ाम देता यह जश्न फूहड़ता में तब्दील होता जा रहा। सदियों से चले आ रहे फागुनी लोकगीतों की जगह कानफाड़ और झमकौआ अश्लील गानों ने ले रखी है। आपसी रिश्तों को तार-तार करते दोहरे मतलबवाले भोंडे भोजपुरी गानों के एल्बम तो अश्लीलता की सारी हदें लांघ चुके हैं। इन परले दर्जे के घटिया गानों पर सेंसर बोर्ड की पाबंदी अब समय की मांग है। इतना ही नहीं, बुरा न मानो होली है के बहाने ख़ासतौर से औरतों को जबरन रंग से सराबोर करना, उन्हें छूना, उन पर कीचड़ फेंकना, पानी के गुब्बारों से चोट पहुंचाना, नशे में धुत्त होना और शर्मसार करनेवाला हुड़दंग कानून-व्यवस्था का सिरदर्द बन सुर्ख़ियों में आ जाता है। कुर्ता फाड़, तो कहीं बेलगाम पानी की बौछार का धमाल हमारी तमीज़ और तहज़ीब पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। कहना न होगा, ये तमाम बेशर्म नज़ारें सोशल मीडिया पर

बेरोक परोस दिये जाते हैं। मजे की बात, यह सब अब आम बात हो गयी है। दूसरे तीज-त्योहारों की मानिंद होली के भी राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण हो जाने से भाईचारे के बजाय आपसी तनाव को शह मिलने लगी है। मन रंगाती होली का बुनियादी मक़सद बुराई पर अच्छाई की जीत (होलिका दहन) के साथ-साथ रिश्तों में मिठास को दोगुना करना होता आया है। लेकिन हमारी चूहादौड़ की ज़िंदगी में इस सांस्कृतिक महोत्सव में अनुशासन और गरिमा का संतुलन बनाये रखना अहम चुनौती बन गया है। यही वजह है, अमनपसंद आम आदमी का जोश-ओ-ख़रोश के साथ होली मनाने का दिल उचट गया है। क्योंकि रंगों और ख़ुशियों का त्योहार बेमजा लगने लगा है।

वैसे भी सूर्य संवेदना पुष्पे, दीप्ति कारुण्यगंधने। लब्ध्वा शुभं होलिकापर्वेऽस्मिन कुर्यात्सर्वस्य मंगलम की मंगलमय कामना अब बातें हैं! बातों का क्या! होली सम्मेलन की आड़ में बार डांसरों को नचवाने की घिनौनी करतूत भी सामने आ गई है। जबकि किसी ज़माने में कथक के थिरकन पर होरी खेलत नंदलाल के सुर आत्मतृप्ति से निहाल कर दिया करते थे। जलती चिताएं और झूमते अघोरियों के बीच बनारस के मणिकर्णिका घाट पर चिता-भस्म से खेली जानेवाली मसान होली पर इस बार भी रार मचा हुआ है। विद्वत परिषद की ओर से फूहड़ता के आरोप पर रोक लगाने की मांग बुलंद है। वहीं दूसरी ओर, उदयपुर में 500 सालों से मेनारिया ब्राह्मणों की मनाई जानेवाली गोली-बारूदों की होली में रातभर गरजते तोपों से उगलते आग के संग-संग झूमते गांववालों के बीच समां बांधती बायलियां गाती हैं वीररस के गीत। ग़ौरतलब है, इस बार ब्रज में अग्रवाल समाज की महिलाओं ने होली का मनोरम आयोजन किया है। सनद रहे, शाहजहां के मुग़लिया दौर में भी होली ईद-ए-गुलाबी या आब-ए- पाशी के नाम से बतौर रंगों की बौछार मनाई जाती रही। दक्षिण भारत का कमन पोडिगई भी रंग बिखेरती होली ही है। आजकल होली के हुड़दंगों का नाजायज़ फ़ायदे लेकर सिर उठाती अमानवीय विकृतियों की असहनीय वारदातें जगजाहिर हैं। ऐसी बेज़ा हरकतें होली पर वे बदनुमा दाग़ हैं, जो इसे बेरंग बना देते हैं। अगरचे यही रवैया चलता रहा, तो आनेवाली पीढ़ियां इसे पावन उत्सव को हुड़दंग ही समझेंगी। मगर तब तक होली का वजूद ही मिट जायेगा। इसलिए समय रहते सामाजिक जागरुकता ही हमारी लाज बचा पायेगी। यह ख़ुशी की बात है, आनंदनगरी तिलोत्तमा कोलकाता में होली के मौके पर हास्य व व्यंग्य सम्मेलन आयोजित करने की शताब्दी प्राचीन समृद्ध परंपरा का सिलसिला आज भी कायम है। नवल जोशी आयोजित राष्ट्रीय हास्य सम्मेलनों में काका हाथरसी (प्रभुलाल गर्ग), डॉ. हरि ओम पवार और अशोक चक्रधर सरीखे चोटी के हास्य कवियों को सुन ठहाके लगाने का जश्न यह शहर मना चुका है। राजकुमार अग्रवाल, सुभाष भरतिया, हिंदुस्तान क्लब और लॉयंस क्लब ऑफ कोलकाता की मेज़बानी आज भी बदस्तूर जारी है। ये बात और है, अब मन रमने की जगह दिखावेपन ने ले ली है। इस बार 1 मार्च को महाराजा अग्रसेन धाम की ओर से धन धान्य ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष हास्य कवि सम्मेलन में पधार रहे हैं डॉ. कुमार विश्वास। संस्कृति सागर के आयोजन में सुरेंद्र शर्मा, चिराग जैन, अरुण जैमिनी शिरकत करेंगे। चेंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री भी कवि सम्मेलन आयोजित कर रहा। शहरी तनाव और उदासी के बीच हंसने-हंसाने की पहल को सलाम!

लोकतांत्रिक और मानवीय समाज के निर्माण के लिए भाषा की आलोचनात्मक समझ जरुरी : पवित्र सरकार

निज संवाददाता : प्रख्यात भाषाविद् पवित्र सरकार ने कहा कि भाषा की गहरी और आलोचनात्मक समझ ही लोकतांत्रिक और मानवीय समाज की आधारशिला है। वे अवनीन्द्र सभागार में आयोजित प्रथम डॉ. आर. एस. चौधरी स्मारक व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान का विषय था "हम भाषा से क्या समझते हैं और हमें क्या समझना चाहिए।" अपने वक्तव्य में प्रो. सरकार ने स्पष्ट किया कि भाषा केवल संप्रेषण का उपकरण नहीं, बल्कि वह एक सजीव सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति है, जो मानव चेतना और सामाजिक संरचनाओं को रूपायित करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध कवि रजत बंद्योपाध्याय ने की। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में उन्होंने भाषा के नैतिक और सौंदर्यात्मक आयामों पर प्रकाश डालते हुए भाषाई बहुलता की रक्षा को बौद्धिकों की जिम्मेदारी बताया। यह व्याख्यान-शृंखला आर एस इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा डॉ. राम सेवक चौधरी की स्मृति में आरंभ की गई है। इस शृंखला का उद्देश्य मानवीय मूल्यों और बौद्धिक विमर्श की परंपरा को सुदृढ़ करना है। स्वागत भाषण में प्रो. राम प्रहलाद चौधरी ने कहा कि तीव्र तकनीकी परिवर्तनों, सांस्कृतिक एकरूपता के दबाव और सामाजिक विखंडन के इस समय में भाषा पर पुनर्विचार एक

गहरी बौद्धिक और नैतिक आवश्यकता है। भाषा पीढ़ियों को जोड़ती है, समाज में सेतु का निर्माण करती है और संघर्षों तथा उपलब्धियों की स्मृतियों को सुरक्षित रखती है। प्रारंभिक वक्तव्य में प्रो. राम आह्लाद चौधरी ने कहा कि यह स्मारक व्याख्यान केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि बौद्धिक उत्तराधिकार और वैचारिक संवाद की एक सार्थक पहल है। उन्होंने डॉ. आर. एस. चौधरी की उस मान्यता को स्मरण किया कि मानव अस्तित्व, सामाजिक गतिशीलता और ऐतिहासिक चेतना भाषा के माध्यम से ही अर्थ ग्रहण करती है। कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तित्वों का सम्मान भी किया गया। सत्र का संचालन अमल कर ने किया। इस अवसर पर चार पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। प्रो. पवित्र सरकार ने राम आह्लाद चौधरी द्वारा रचित बंगला पुस्तक 'पांच स्रष्टा: एक मानविक स्वप्न' का लोकार्पण किया। अर्चना पांडेय और राम आह्लाद चौधरी संपादित पुस्तक 'प्रेमचंद के सृजनात्मक मानदंड का सौंदर्य' का लोकार्पण रजत बंद्योपाध्याय ने किया। राम आह्लाद चौधरी की कृति 'सौंदर्य और भाषा: समय, समाज और सृजन' का विमोचन उपासना सरकार ने किया। श्यामल सेन गुप्ता द्वारा लिखित तथा राम आह्लाद चौधरी द्वारा अनूदित 'गांधी हत्या का नेपथ्य' का लोकार्पण प्रो. सरकार ने किया। कार्यक्रम के उपरांत बहुभाषिक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बांग्ला, हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, अरबी और फारसी के कवियों ने भाग लिया। संचालन अमल कर और संजीव कुमार सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. अर्चना पांडेय ने किया तथा मंच संचालन डॉ. पार्थ प्रतिम पांजा ने किया।

अजब-गजब

चीन में कुछ खास अंदाज में मनाते है लूनर न्यू ईयर

साल भर के प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों को मिलता है बंपर बोनस व गिफ्ट

निज संवाददाता : चीन में लूनर न्यू ईयर यानी चंद्र नव वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर बंपर बोनस और गिफ्ट बांटने की प्रथा है। अब इस त्योहार के नजदीक आते ही चीन में कई कारोबारी बोनस बांटने में जुटे हैं। कई फर्में कर्मचारियों को नकद रकम दे रही हैं। इतना अधिक कैश बोनस मिल रहा है कि उसे हाथों में संभालना मुश्किल है। बोनस मिलने के बाद कर्मचारी इन पैसों को बॉक्स, बैग में भरकर ले जाते हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।यह परंपरा चीनी न्यू ईयर से पहले चरम पर पहुंच जाती है। इस दौरान चीनी फर्म साल भर के प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों को पुरस्कृत करती हैं। नकद बोनस को एक रोचक खेल में बदल दिया जाता है। हेनान प्रांत की एक क्रेन निर्माण कंपनी ने 50-70 मीटर लंबी टेबल पर लाखों युआन के नोट बिछा दिए और कर्मचारियों को 15 मिनट में

जितना गिन सकें, उतना ले जाने की बात कह दी। चीन में यह परंपरा बड़ी अजीब है। अगर किसी ने सही काउंटिंग नहीं की तो उसकी गलत गिनती पर जुर्माना भी लगाया जाता है।रिपोर्ट के मुताबिक एक कर्मचारी ने 97,800 युआन करी यानी 14,500 अमेरिकी डॉलर तक गिन लिए। कंपनी ने कुल 100 मिलियन युआन यानी 14 मिलियन डॉलर का बोनस पूल बनाया, जिससे 5,000 कर्मचारियों को लाभ हुआ। एक अन्य फर्म ने 60 मिलियन युआन नकद बांटे, जहां कर्मचारी नोटों के पहाड़ से पैसे उठा रहे थे। जियांग्शी प्रांत में किसानों को भी रिकॉर्ड बोनस मिले, जहां 21.29 मिलियन युआन के ढेर बनाए गए। ये बड़े बोनस आर्थिक सुधार, मजबूत प्रदर्शन और कर्मचारियों को बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा हैं। चीन में ऐसा मनता है न्यू ईयर।चीनी संस्कृति में साल के अंत का बोनस घर लौटने और परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए अहम होता है। हालांकि सभी फर्म और कंपनियां नकद नहीं देतीं कुछ बैंक ट्रांसफर या गिफ्ट्स देती हैं, लेकिन नकद ढेर वाली घटनाएं सबसे ज्यादा चर्चा बटोरती हैं। यह ट्रेंड दिखाता है कि चीन में कुछ क्षेत्रों में आर्थिक रिकवरी मजबूत है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और टेक सेक्टर में कर्मचारी खुश हैं। लूनर न्यू ईयर 2026 में कई परिवारों के लिए बड़े तोहफे बन रहे हैं।

तकनीक और प्रकृति के बीच संतुलन की अनूठी मिसाल

जापान ने पेश किए आलू के स्टार्च से बने बैग

निज संवाददाता : प्लास्टिक बैग की समस्या से निपटने को जापान ने बेहद उपयोगी समाधान पेश किया है। जापान में ऐसे किराने के बैग लॉन्च किए गए हैं, जो पूरी तरह आलू के स्टार्च से बनाए गए हैं। दिखने और उपयोग में बिल्कुल प्लास्टिक जैसे मजबूत इन बैगों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पारंपरिक प्लास्टिक की तरह वर्षों तक कचरे के ढेर में पड़े नहीं रहते, बल्कि पानी के संपर्क में आते ही सहज रूप से घुल जाते हैं। सदियों तक समुद्र में तैरते रहने वाले प्लास्टिक बैग अक्सर कछुओं, मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के लिए घातक साबित होते हैं, क्योंकि वे इन्हें भोजन समझकर निगल लेते हैं। जापान में विकसित यह नई सामग्री इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। खास बात यह है कि यह स्टार्च-आधारित बैग ठंडे पानी में भी पूरी तरह टूट जाता है। यदि कोई समुद्री जीव इन्हें गलती से निगल ले, तो यह उसके शरीर में बिना किसी नुकसान के प्राकृतिक रूप से घुल जाएगा। बैग के घुलने के बाद पानी में न तो कोई जहरीला रसायन बचता है और न ही माइक्रोप्लास्टिक। यह नवाचार दिखाता है कि किस तरह तकनीक और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर पर्यावरण अनुकूल समाधान विकसित किए जा सकते हैं। आलू के स्टार्च से बना यह बैग न सिर्फ मजबूत है और वजन उठाने में सक्षम है, बल्कि उपयोग के बाद इसे नष्ट करना भी बेहद आसान है। इससे प्लास्टिक कचरे का बोझ कम हो सकता है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी बड़ा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जापान का यह कदम अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। यह मॉडल दर्शाता है कि यदि रोजमर्रा की वस्तुओं के उत्पादन में पर्यावरणसुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, तो धरती को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के

पहली फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' बनाने में लगे थे 6 महीने

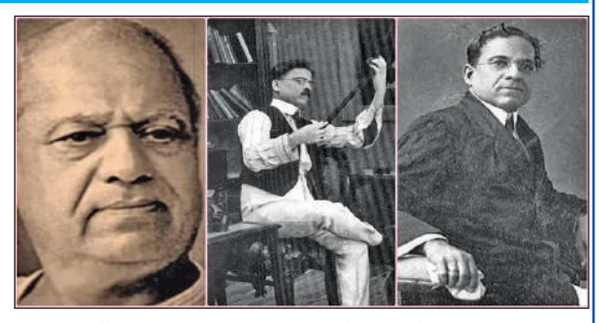

निज संवाददाता : भारतीय सिनेमा के पिता कहे जाने वाले फिल्ममेकर दादा साहब फाल्के ने भारतीय सिनेमा की पहली स्क्रिप्ट लिखी थी। उन्होंने फिल्म कंपनी की स्थापना करने के साथ भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। यह भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म थी।

जन्म और परिवार

बंबई प्रेसीडेंसी के त्रिंबक में एक मराठी परिवार में 30 अप्रैल 1870 को दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ था। उनका असली नाम धुंडिराज फाल्के था। इनके पिता का नाम गोविंद सदाशिव फाल्के था, जोकि संस्कृत के विद्वान और हिंदू पुजारी थे। वहीं उनकी मां का नाम द्वारकाबाई था। उन्होंने अपनी शुरूआती शिक्षा पूरी करने के बाद मैट्रिक की पढ़ाई बॉम्बे में पूरी की। फिर 1855 में उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से ड्राइंग का कोर्स पूरा किया। साल 1890 में उन्होंने एक कैमरा खरीदा और मुद्रण व प्रसंस्करण के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया।

फिल्मी सफर

साल 1913 में दादा साहब फाल्के ने फिल्म राजा हरिश्चंद्र नामक पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी। वह एक निर्देशक नहीं बल्कि एक जाने-माने निर्माता और स्क्रीन राइटर भी थे। उन्होंने 19 साल के फिल्मी करियर में करीब 95 फिल्में और 27 शॉर्ट फिल्में बनाई थीं। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने के बाद दादा साहब फाल्के को फिल्म बनाने का ख्याल आया। इस फिल्म ने उन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी थी कि उन्होंने फिल्म बनाने की ठान ली। हालांकि यह काम इतना भी आसान नहीं था। वह एक दिन में चार-पांच घंटे सिनेमा देखते, जिससे कि फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीख सकें। बताया जाता है कि उनकी पहली फिल्म का बजट करीब 15 हजार रुपए था। इस फिल्म के लिए दादा साहब ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उस दौर में फिल्म बनाने के जरूर उपकरण सिर्फ इंग्लैंड में मिलते थे। इंग्लैंड जाने के लिए दादा साहब फाल्के ने अपनी पूरी जमा-पूंजी लगा दी थी। पहली फिल्म बनाने में उनको करीब 6 महीने का समय लग गया था। दादा साहब फाल्के की आखिरी मूक फिल्म सेतुबंधन थी। 16 फरवरी 1944 को दादा साहब फाल्के ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था।

असम के कामरूप का अनोखा मंदिर

जहां कछुए चढ़ाने से पूरी होती है मन्नत

निज संवाददाता : भारत के असम राज्य के कामरूप जिले में स्थित श्री हयग्रीव माधव मंदिर न सिर्फ अपनी वास्तुकला बल्कि अनोखी परंपरा के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। यह मंदिर मणिकूट पर्वत पर बना है। श्री हयग्रीव माधव मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए कई सदियों से आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। भारत के असम राज्य के कामरूप जिले के हाजों में भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम श्री हयग्रीव माधव मंदिर है। जोकि भगवान श्रीहरि विष्णु के हयग्रीव अवतार यानी की घोड़े के सिर वाले अवतार की पूजा होती है। यह मंदिर न सिर्फ अपनी वास्तुकला बल्कि अनोखी परंपरा के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। यह मंदिर मणिकूट पर्वत पर बना है। श्री हयग्रीव माधव मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए कई सदियों से आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। इस मंदिर की खास बात यह है कि श्रद्धालु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए कछुए का चढ़ावा करते हैं।

मंदिर का पौराणिक महत्व

इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यहां पर भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु ने इस स्थान पर मधु-कैटभ नामक दो राक्षसों का वध किया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1583 में कोच राजा रघुदेव नारायण द्वारा कराया गया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह 100 साल से भी ज्यादा प्राचीन काल के ध्वस्त मंदिर का पुनर्निर्मित हैं। श्री हयग्रीव माधव मंदिर पत्थरों का बना है और मंदिर की दीवारों पर हाथियों और अन्य पौराणिक आकृतियों की सुंदर नक्काशी की गई है।

कछुए अर्पित करने की परंपरा

इस मंदिर की विशेषता यहां का माधव पुखुरी है।

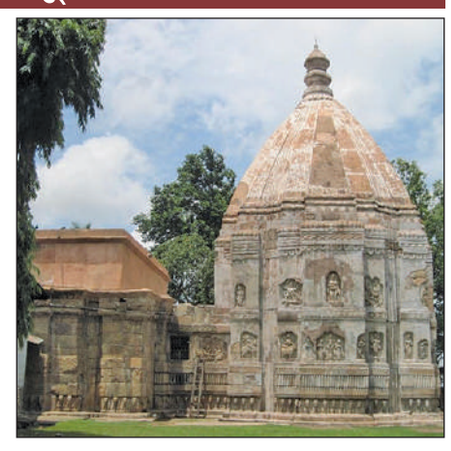

इस तालाब में सैकड़ों की संख्या में दुर्लभ प्रजाति के कछुए रहते हैं। परंपरा है कि भक्त अपनी इच्छा पूरी होने पर या भगवान को श्रद्धा अर्पित करने के लिए कछुओं को भोजन कराते हैं या फिर तालाब में कछुए छोड़ते हैं। कछुओं को भगवान का एक रूप माना जाता है। वहीं स्थानीय लोग इन कछुओं की सुरक्षा का खास ध्यान रखते हैं और इनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

बौद्ध धर्म से जुड़ाव

इस मंदिर की एक और खासियत यह है कि यहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि भारी संख्या में बौद्ध अनुयायी भी आते हैं। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि यह वह जगह है, जहां भगवान बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। जिस कारण बौद्ध समुदाय के लोग इस मंदिर को बेहद पवित्र मानते हैं और वह इसको महामुनी का मंदिर कहते हैं। श्री हयग्रीव माधव मंदिर की संस्कृति, धर्म और वन्यजीव संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है। यहां की शांति और सदियों पुरानी परंपराएं इसको भारत के अन्य मंदिरों से अलग बनाती हैं।

एक छोटे से पैर का स्केच, जिसने सदियों तक गुमनामी में समय बिताया

निज संवाददाता : न्यूयॉर्क में एक छोटा सा स्केच क्रिस्टीज करोड़ों डॉलर में बिक गया। इस स्केच की नीलामी इतनी ज्यादा इसलिए लगी, क्योंकि नीलामी घर ने इसे महान कलाकार माइकल एंजेलो की कृति के रूप में प्रमाणित किया था। यह मामूली सा दिखने वाला स्केच एक पैर को दर्शाता है, जिसमें एड़ी जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई है और नीचे उसकी परछाईं की हल्की सी रूपरेखा बनी है। जब इसके मालिक ने इसकी तस्वीर ऑनलाइन वैल्यूएशन पोर्टल पर भेजी थी, तब उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनके पास मौजूद यह ड्रॉइंग कला इतिहास की एक बेहद कीमती धरोहर साबित होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में हुई क्रिस्टीज की नीलामी में यह स्केच फीस समेत 2.72 करोड़ डॉलर यानी करीब 246 करोड़ रुपए में बिकी। नीलामी से पहले इसकी अनुमानित कीमत कम आंकी गई थी, लेकिन जैसे ही यह साफ हुआ कि यह ड्रॉइंग खुद माइकल एंजेलो ने बनाई थी, इसके लिए जबरदस्त बोली लगने लगी। आखिरकार यह अपने अनुमानित मूल्य से करीब 20 गुना ज्यादा कीमत पर बिकी और नीलामी में बिकने वाली माइकल एंजेलो की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई। विशेषज्ञों के मुताबिक माइकल एंजेलो ने यह स्केच लाल चॉक से बनाया था। यह दरअसल वैटिकन स्थित सिस्टीन चैपल की छत पर बनाई

246 करोड़ रुपए में हुआ नीलाम

गई प्रसिद्ध फ्रेस्को पेंटिंग की तैयारी के दौरान बनाया गया प्रारंभिक रेखाचित्र था। माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत को 1508 से 1512 के बीच चित्रित किया था, जिसे कला जगत की सबसे महान कृतियों में गिना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सिस्टीन चैपल की छत पर बनी 'लिबियन सिबिल' की आकृति को ध्यान से देखा जाए, तो उसमें एक विशाल महिला आकृति दिखाई देती है, जो पीछे की ओर मुड़कर एक किताब रखने की मुद्रा में है। उसी आकृति के पैर की स्थिति बिल्कुल इसी स्केच से मेल खाती हैउंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई, एड़ी जमीन से उठी हुई और नीचे हल्की सी परछाईं। यही समानता इस स्केच को माइकल एंजेलो की कृति साबित करने का सबसे अहम सुराग बनी। हालांकि यह ड्रॉइंग अब तक कला इतिहासकारों के लिए अज्ञात थी, लेकिन इसकी प्रामाणिकता को लेकर कई ठोस संकेत मिले। ड्राइंग के निचले बाएं कोने में माइकल एंजेलो का नाम लिखा है, और विशेषज्ञों के मुताबिक यह लिखावट ठीक वैसी ही है जैसी न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में मौजूद उनकी अन्य कृतियों पर मिलती है। क्रिस्टीज के मुताबिक महीनों की गहन जांच और रिसर्च के बाद माइकल एंजेलो के प्रमुख विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से माना कि यह स्केच उन्हीं की बनाई हुई है। बताया गया है कि यह स्केच पिछले 200 सालों से एक ही परिवार के पास था। 18वीं सदी में स्विट्जरलैंड के राजनयिक आर्मां फ्रांस्वा लुई द मेस्ट्राल द सेंट-सैफोरिन ने इसे यूरोप की यात्राओं के दौरान हासिल किया था। उस समय वह डेनमार्क के राजा के लिए काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने यह स्केच अपने भतीजे को सौंप दिया और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यह ड्रॉइंग उसी परिवार में सुरक्षित रही। कला विशेषज्ञों का कहना है कि यह बिक्री इस बात का सबूत है कि कला की दुनिया में कभी-कभी सबसे छोटी और साधारण दिखने वाली चीजें भी असाधारण मूल्य रखती हैं। एक छोटे से पैर का स्केच, जिसने सदियों तक गुमनामी में समय बिताया, आज माइकल एंजेलो की प्रतिभा का अनमोल प्रमाण बनकर दुनिया की सबसे महंगी ड्रॉइंग्स में शामिल हो गया।

होली के रस की बही,
सरस धरा पे धार।
ऊँच नीच सब भूल कर,
करें परस्पर प्यार।।

होली हुड़दंग, बुरा न मानो होली है...

समाज की विशिष्ट हस्तियां

सब्यसाची दत्त	– देखची
कृष्णा चक्रवर्ती	– काम बाकी है
सुजीत बोस	– मेजर साहब
राजेश चिड़िमार	– सर्व शिक्षा अभियान
बाबूलाल धनानिया	– हंसी की फुहार
गौरधन निगानिया	– कुछ-कुछ होता है
विजय मनोहर तिवारी	– हरफनमौला
विनोद जी दुग्गड़	– दिमाग में सब है
राजकुमार जैन (तपसिया)	– कलम की ताकत
वेद प्रकाश अग्रवाल (तपसिया)	– हिसाब का पक्का
उज्जवल उपाध्याय (ईएमटीए)	– हौसले बुलंद
सौगत उपाध्याय (ईएमटीए)	– जो होगा देखा जाएगा
विशाल अग्रवाल (राजेश मेडिकल)	– मधुर वाणी
श्रीमती संतोष अग्रवाल (बोलतोता)	– हार नही मानूंगी
मुरारी लाल दीवान	– कर्मठ पहचान
राहुल दीवान	– पिता के पदचिन्हों पर
गुरुजी भवानीप्रसाद महापात्रा (पुरी)	– प्रभू तेरी शरण में
अजीत तुलस्यान (सीए)	– नयन मटक के चलूंगा
राजेश कुमार अग्रवाल (सीए)	– दिमाग से जीत
विवेक दीवान	– समय का पक्का
विवेक बैद	– सबसे ज्यादा व्यस्त
राजू जैन (एड-वेल्थ)	– शेयर खरीदने हैं
संजय अग्रवाल	– सुलझे हुए विचार
गोबिंद अग्रवाल	– काका के दीवाने
शुभम अग्रवाल	– ईश्वर कृपा
तन्मय जैन	– खुशियों की दास्तां
सुरेश गुप्ता	– हम होंगे कामयाब
उमेश राय	– ईद का चांद
सुभाष जैन	– हम भी हैं जोश में
द्वारका प्रसाद अग्रवाल	– दुःख का पहाड़
श्यामलाल हांसीवाल	– गंभीर आत्मा
डा. राजू विश्वास	– धुरंधर
ओम प्रकाश बेरीवाल	– शांति दूत
गोविंद राम अग्रवाल	– सेवा भावना
अनिल शर्मा	– युवा जोश
अनिल गोयल	– छुपा रुस्तम
राजीव जायसवाल	– काम बाकी है
मनोज सिंह पराशर	– अड़ियल खोपड़ी
राजेश सिन्हा	– कोई बात नहीं
राजीव सिन्हा	– लक्ष्मी नदारद
कन्हैया लाल कोठारी	– कंजूस
विनोद गट्टानी	– सब ठीक है भाया
राजीव चंगोईवाला	– राम भरोसे
कमल गांधी	– हिंसा नरम गरम
गौरव बागला	– टोपीबाज
संजय अग्रवाल	– नोटबंदी
सुशील ओझा	– अतिथि देव भवः
विकास पोद्दार	– मेरे हमदम मेरे दोस्त
मनोज तोदी	– रखवाला
बाबूलाल बंका	– सुपर फास्ट
अशोक ओझा	– आगे बढ़ने की चाह
संजीव शर्मा	– सोशल स्टार
रामचंद्र बड़ोपोलिया	– वादा निभायेंगे
रमेश लाखोटिया	– जेंटलमैन
मदन गोपाल राठी	– गोल मटोल
संदीप गर्ग	– संस्कारी पुरुष
कमलेश केजरीवाल	– आर्गनाइजर
महेंद्र कुमार अग्रवाल	– दीवाना-मस्ताना
इंद्रकुमार डागा	– सपने सच होंगे
सुशील कुमार मूंधड़ा	– हुड़दंगी
विश्वनाथ भुवालका	– मुझे भी साथ ले ले
विनोद गट्टानी	– संस्कारी सज्जन
सत्यनारायण सोनी	– आश्वासन की दुकान
अशोक तोदी	– अगली बार
ललित प्रह्लादका	– पहरेदार
रामबाबू धनानिया	– संभाल लेंगे
ललित बेरीवाल (श्याम स्टील)	– रंगीला प्रेम
रतन माहेश्वरी	– पोस्टमैन
कैलाश चंद्र तोषनीवाल	– सिरदर्द
सुशील कुमार माहेश्वरी	– सरदार
पवन बंसल	– देशी बाबू
रेणु कासट	– नारी शक्ति
राजकुमार चांदवासिया	– जिम्मेदार
लक्ष्मीनारायण गुप्ता	– खेल-खेल में
रामकिशन गोयल	– कभी नहीं
विनोद अग्रवाल	– रफ्तार का सौदागर
देवश्लोक शर्मा	– डॉक्टर साहब
हरि प्रसाद बुधिया	– अब क्या बोले
बृजमोहन मोहता (अजंता टेक्सटाइल)	– हवा हवाई
डॉ. अर्क बनर्जी (बेलव्यू)	– मैं हूं ना
साकेत मोदी (लक्स कोजी)	– अंदर की बात है
भंवर लाल राठी	– बेमिशाल
द्वारका प्रसाद कासट	– आशियाना
हेमंत मर्दा	– नारी शक्ति
राजेंद्र खंडेलवाल (धनवंतरी)	– जवां दिल
पंकज पोद्दार (अभिनंदन क्लिनिक)	– गंभीर आत्मा
श्री पाटोदिया (मणि स्कायर)	– जगह खाली है
आर.आर.अग्रवाल (ज्वेलर्स प्रा.लि.)	– चकाचौंध साम्राज्य
श्वेता नाहटा	– बुलंदी पर
अमर भरतिया	– हाईफाई
संजीव सरावगी (लेमन बाथम)	– किस्मत की कुंजी
स्वपन कांति घोष (पटेल नगर मिनरल)	– अच्छा स्वास्थ्य
कैलाश कासट	– सज्जन
शशिकांत कासट	– तेजस्वनी
एल. पी पंसारी (पंसारी मसाला)	– शुद्धता की पहचान
चन्द्रप्रकाश नाहटा	– भुलक्कड़
अशोक गुप्ता	– नटवरलाल
आलोक बाजोरिया (गणेश काम्प्लेक्स)	– बेजोड़
रतन चौधरी (पंचवटी)	– तेज तर्रार
अरुण संचेती (संचेती ग्रुप)	– प्रेमी
उत्कर्ष बंसल (उत्कर्ष स्टील)	– नयी खोज
डॉ. नवमिता पांडे (फेमिली लाइफ फर्टिलिटी)	– उंची मंजिल
आनंद सुरेका (आधुनिक इंफ्रा)	– सीधी बात
ललित कांकरिया (जैन ग्रुप)	– कर्मठ
डॉ. मधुसूदन खंडेलवाल (मारवाड़ी अस्पताल)	– बहुआयामी
रवि लोहिया (डॉलर)	– आराम का मामला
सुनील पटवारी (रश्मि ग्रुप)	– नाम ही काफी है
विकास अग्रवाल (रूपा)	– ये अंदर की बात है
रंजीत छट्टी (एसबीके रंजीत)	– दिग्गज
हरि शर्मा (फोर्ड ग्रुप)	– किंग

मेरी पड़ोसन फुलवा तोरैं,माली से बतियायँ देख पड़ोसी, नैनमटक्का, ज़ोर ज़ोर चिल्लायं जोगीरा सरारारा.....

राजा बाइन (बाइन ट्रावेल्स)	– हमसफर
ओम प्रकाश पांडे (पांडे कन्सट्रक्शन)	– बुलंदी
अविनाश अग्रवाल (कैप्टन टीएमटी बार)	– स्ट्रांग
अनुराग अग्रवाल (सीटी सर्विस)	– नयी खोज
विशाल कपूर	– रसिया
अनिल सोमानी	– ऊंची दुकान फीका पकवान
पी. सी. चन्द्रा	– सोने पे सुहागा
सुरेन जालान	– ऊंचे इरादे
एन. जी. खेतान	– आगे की सोच
हरि प्रसाद कानोड़िया	– संस्कारी
जे. पी. चौधरी	– धार्मिक
देवेन्द्र मंत्री	– प्रेसीडेंट
पवन धूत (धूत ग्रुप)	– सुलझा हुआ
सुरेन्द्र दुगड़ (बीएमडी)	– नहले पर दहला
दीपक जालान (लिंक)	– बड़ी योजना
मिराज शाह	– लगन
विशाल झाझड़िया	– वापसी
बजरंग लाल खेरुका	– कुशल
संजीव कुमार पटवारी (रश्मि मेटालिक्स)	– मंथन
मदन मोहन मोहनका (टेगा इंडस्ट्रीज)	– शुभचिंतक
विक्रम सोमानी (सेरा)	– कलाप्रेमी
अतुल चुड़ीवाल (कृषि रसायन एक्सपोर्ट)	– नयापन
परीक्षित मूंधड़ा	– धैर्य
पुरुषोत्तम दास गोयल	– भरपूर
दीपक गोयल	– ईश्वर कृपा
विवेक सरावगी (बलरामपुर चीनी मिल)	– आगे बढ़ो
एम. के. धानुका (धानुका एग्रीटेक)	– ऑल इज वेल
बिठ्ठलदास मूंधड़ा	– कूल-कूल
कुंज बिहारी अग्रवाल (रूपा)	– पद्मश्री
घनश्याम प्रसाद शोभासरिया	– सादगी
दिलीप जायसवाल (एचएचआई)	– अडिग
किशोर बियानी (फ्यूचर रिटेल्स)	– संतोष
शाश्वत गोयनका (आरपीजी)	– छप गया
सी. के. धानुका (धनशेरी टी)	– डाउट
गोपाल राठी	– जिंदा दिल
रवि शर्मा	– मस्तमौला
राजकुमार केडिया	– जौहरी की परख
मंजु राठी	– दम है

कुछ खास और अनोखी होती है उत्तराखण्ड की कुमाऊंनी होली

सिर्फ रंगो का त्योहार नहीं, मेल-मिलाप और परंपराओं का है संगम

निज संवाददाता : उत्तराखण्ड में कुमाऊंनी होली प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से होती है, लेकिन असली होली उस दिन से होती है जब सबसे पहले भगवान को रंग लगाया जाता है। मंदिर से शुरू होकर होली घर-घर पहुंचती है। बैठ और खड़ी होली इसके मुख्य रूप हैं। कुमाऊं क्षेत्र में मनाई जाने वाली कुमाऊंनी होली खास और अनोखी होती है। जहां शहरों में होली अक्सर एक या दो दिन का त्योहार होती है, वहीं पहाड़ों में यह कई दिनों तक चलने वाला सांस्कृतिक उत्सव बन जाती है। यहां होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी मेल-मिलाप, संगीत और परंपराओं का संगम है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुमाऊंनी होली की शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है। होली के गीत गाने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले भगवान की होली गाई जाती है, फिर धीरे-धीरे यह होली

एक-एक करके लोगों के घरों तक पहुंचती है। कुमाऊं में होली मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है बैठ होली और खड़ी होली। बैठ होली में लोग बैठकर शास्त्रीय संगीत की धुनों पर होली गाते हैं। इसमें हारमोनियम और तबले का इस्तेमाल होता है। वहीं खड़ी होली में लोग खड़े होकर, ढोलक और मंजीरे के साथ नाचते-गाते हुए घर-घर जाते है, जो लोग होली गाते हैं, उन्हें होल्यार कहा जाता है। वे हर शाम अलग-अलग घरों में जाकर होली गाते हैं। घरों में उनका स्वागत गुड़ और सौंफ से किया जाता है, जो मिठास और प्रेम का प्रतीक है। पहाड़ों का माहौल इस दौरान बहुत शांत, सौम्य और प्रेम से भरा रहता है।रिपोर्ट के मुताबिक एक पहाड़ी महिला बताया कि उन्हें होली का बहुत इंतजार रहता है। हम लोग इधर-उधर जाकर होलियां गाते हैं। केवल होली ही नहीं, बल्कि झोड़े भी गाते हैं। झोड़ा भी कुमाऊं का प्रसिद्ध लोकगीत और नृत्य है, जो होली के समय खास उत्साह के साथ गाया जाता है। महिलाएं रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर पूरे उत्साह से इस पर्व में भाग लेती हैं। कुमाऊंनी होली केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पहाड़ी सर्दियों के अंत और नई फसल के मौसम की शुरुआत का भी संकेत देती है। लंबे ठंड के बाद जब बसंत आता है, तो होली के गीतों के साथ प्रकृति भी मुस्कुराने लगती है। इस तरह कुमाऊंनी होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि पहाड़ों की संस्कृति, संगीत और आपसी प्रेम का जीवंत उत्सव है।

नई बहू क्यों ससुराल में नहीं मनाती पहली होली?

कारण जानकर रह जाएंगे हैरान

निज संवाददाता : होली के पावन पर्व में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस साल 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाएगा। इसके बाद 4 मार्च को रंगों का त्योहार मनाया जाएगा। हर साल देशभर में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली के दिन लोग आपसी मतभेद को भूलकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। हर त्योहार कई मायने में बहुत खास होता है। हर पर्व का अपना महत्व होता है। साथ ही हर त्योहार की अलग-अलग परंपराएं और मान्यताएं भी होती हैं। होली की भी कई परंपराएं हैं। इन्हीं में से एक है शादी के बाद नई बहू के ससुराल में होली न मनाने की परंपरा। ये परंपरा देश के कई हिस्सों में मानी जाती है, जहां शादी के बाद पहली होली के समय बहू को मायके भेज दिया जाता है। आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे का कारण। विवाह के बाद नई बहू को होली के त्योहार पर

मायके भेज देने को लेकर कई मान्यताएं और धारणाएं हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, अगर विवाह के बाद नई बहू ससुराल में पहली होली मनाती है, तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। उत्तर भारत में यह प्रथा काफी चलन में है, इसीलिए विवाह के बाद नई बहू को होली से पहले मायके भेज दिया जाता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर सास-बहू साथ में होलिका दहन देखती हैं, तो संबंधों में खटास आती है। इसलिए भी होली के पहले नई बहू को मायके भेजने की परंपरा चली आ रही है। एक मान्यता है कि विवाह के बाद नई बहू के पहली होली पर ससुराल में रहने से घर में क्लेश बढ़ता है। आपसी संबंधों में भी मनमुटाव आता है। इस प्रथा के पीछे एक और वजह छिपी हुई है। दरअसल, शादी के बाद अक्सर बहू के लिए कई प्रतिबंध और मर्यादाएं होती हैं, जिनमें उसे रहना होता है। ऐसे में सबके सामने पति के साथ होली खेलना काफी असहज कर सकता है। इसलिए कभी भी पहली होली बहू अपने मायके में मनाती है।

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर विवाद

डोम राजा ने दी दाह संस्कार रोकने की चेतावनी

निज संवाददाता : उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट पर दशकों से मनाई जा रही मसान की होली इस साल विवादों में घिर गई है। काशी के डोम राजा परिवार के वंशज विश्वनाथ चौधरी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि, यह परंपरा शास्त्रसम्मत नहीं है, जो श्मशान की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि, यदि आयोजन नहीं रोका गया तो वे महाश्मशान में में दाह संस्कार रोकने को बाध्य होंगे। उनके ज्ञापन सौंपने के बाद प्रशासन असमंजस की स्थिति में है। मान्यताओं के मुताबिक, भगवान शिव विवाह के पश्चात रंगभरी एकादशी पर माता गौरी को काशी लाए थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शिव के गण बारात में नहीं जा सके, जिससे वे आहत हुए। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए महाश्मान में चिता की राख से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। बीतते समय के साथ अघोरी और

तांत्रिक परंपराओं से जुड़ा यह आयोजन विस्तार होते चला गया। साल 2009 के बाद बाबा महाश्मशान मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के प्रशासक गुलशन कपूर ने इसे व्यवस्थित रूप दिया, जिसके बाद यग आयोजन देश के साथ विदेश में भी काफी चर्चा में रहा। हर साल हजारों लोग इस भव्य नजारे को देखने के लिए पहुंचते हैं, जिसका पंचांगों में भी उल्लेख है। विश्वनाथ चौधरी के मुताबिक, मसाना की होली का स्पष्ट रूप से कोई धार्मिक आधार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, आयोजन के दौरान नशे में धुत लोग हंगामा करते हैं, शवों के समक्ष अनुचित व्यवहार करने के साथ महिलाएं व नाबालिग वीडियो बनाते नजर आते हैं, जिससे श्मशान की पवित्रता भंग होती है। श्री काशी विधिवत परिषद के संगठन मंत्री प्रो. विनय कुमार पांडे ने इसे शास्त्रों के खिलाफा बताया है। उन्होंने कहा कि, शास्त्रों में महिलाओं और बच्चों को श्मशान घाटों में प्रवेश वर्जित माना गया है। वहीं आयोजन से जुड़े गुलशन कपूर ने तर्क देते हुए कहा कि, काशी खुद अपने आप में महाश्मशान है, जहां मौत को भी उत्सव के रूप में देखा जाता है। उनके मुताबिक, वेद और शास्त्रों के साथ-साथ तंत्र और अघोर परंपराओं में भी इसकी मान्यताएं हैं, जिस नजरिए से यह आयोजन सही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि, जब अन्य घाटों पर होने वाले आयोजनों में डोम राजा परिवार की भागीदारी होती है, तो यहां किस बात का विरोध किया जा रहा है। फिलहाल काशी का प्रशासन दोनों ही पक्षों की दलीलों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में है, जबकि मसाना की होली को लेकर बहस तेज होते जा रही है।

स्वामी मोहता पब्लिशिंग हाउस के लिए, प्रकाशक, मुद्रक : अजय कुमार मोहता द्वारा अरिहंत मुद्रा, 61, सूर्यसेन स्ट्रीट, कोलकाता-700009 से मुद्रित एवं प्रकाशित। **संपादकीय कार्यालय :** 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, (क्लाइब रो), 5बी मंजिल, रूम नं. 9, कोलकाता-700001, **स्थानीय कार्यालय :** 28-5 कन्वेंट रोड, मौलाली, कोलकाता-700014। **संपादक : अजय कुमार मोहता,** मो. 9830045693, E-mail-gambheersamachar@gmail.com. Website. www.gambheersamachar.in (प्रकाशित रचनाओं के चयन, संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी, सभी कानूनी विवाद के लिए कोलकाता न्याय क्षेत्र)